

माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल और जसपाल सिंह के समक्ष  
चंडीगढ़ डेवलपर्स लिमिटेड, करनाल — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा की स्थिति और अन्य — उत्तरदाताओं

**2014** की सीडब्ल्यूपी नंबर **5730**

22 अप्रैल 2015

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद. 226, 227, 246, 366(29-ए) (बी), अनुसूची 7, सूची 2, प्रवेश 54 — हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 — Ss 2 (1) (zg), 9 और 42 — हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 — सूत्री 25 और 49 — CBEC परिपत्र दिनांक 7.5.2003, 4.6.2003 और 10.2.2014 — द्वारा निर्मित फ्लैटों की बिक्री पर भूमि के कॉड पर वैट विकासशील फ्लैट — याचिकाकर्ता डेवलपर के व्यवसाय में लगे हुए थे अपार्टमेंट-स्टफ्लैट-स्टुडिओ का विकास और बिक्री — परिपत्र दिनांक 7.5.2013 को डेटिंग जारी की गई थी कि डेवलपर्स समझौतों में प्रवेश कर रहे थे निर्मित अपार्टमेंट या फ्लैटों की बिक्री के लिए वैट — के लिए प्रभार्य थे नतीजतन, बनाने के संबंध में परिपत्र दिनांक 4.6.2013 जारी किया गया था बिल्डरों और डेवलपर्स पर आकलन — इसके बाद, vide परिपत्र दिनांक 10.2.2014, परिपत्र दिनांक 7.5.2013 विविध था और वैट लगाने के लिए भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया था — याचिकाकर्ताओं का तर्क यह था कि भूमि कॉड पर कर लगाना था असंवैधानिक — इसलिए, उन्होंने धारा 9 की वैधता को चुनौती दी और वैट अधिनियम के 42 — हेल्ड कि, एक फ्लैट बनाने के लिए अनुबंध एक माल की बिक्री का तत्व — भवन अनुबंध कार्यों की प्रजातियां हैं अनुबंध — वैट लगाने के उद्देश्य से, अचल संपत्ति का मूल्य (जैसे, भूमि का मूल्य) और श्रम या सेवा या फ्लैट की बिक्री के समझौते में प्रवेश करने से पहले किए गए किसी भी अन्य शुल्क को बाहर रखा जाना है समझौते के मूल्य से — नतीजतन, नियम 25 (2) को आयोजित किया जाएगा केवल तभी मान्य होगा जब राज्य सरकार नियमों में आवश्यक परिवर्तन लाए उपरोक्त टिप्पणियों के साथ सहमति — आगे, अधिनियम की धारा 42, 2003 के हिस्से में विफलता की स्थिति में केवल राजस्व का ब्याज सुरक्षित है के संबंध में कर के अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए उप-ठेकेदार ठेकेदार के साथ लेनदेन; इस प्रकार, धारा 42 मनमाना नहीं है — अनुभाग 9, नियम 49 और परिपत्र दिनांक 10.2.2014 के साथ पढ़ें रचना योजना के तहत कर का निर्धारण जो वैकल्पिक है और रचना योजना का चयन करके, डीलर को विभिन्न लाभ मिलते हैं और इस प्रकार, धारा 9 पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है.

ये निर्धारित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सिद्धांतों को क्रिस्टलीकृत किया, दूसरे शब्दों में, यह माना गया था कि समझौते के बीच

24 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

प्रमोटर / बिल्डर / डेवलपर और फ्लैट क्रेता एक फ्लैट और निर्माण करने के लिए इसके बाद जमीन के कुछ हिस्से के साथ फ्लैट बेच दें, इसमें गतिविधि शामिल है पार्टियों में से एक कार्य करने या निष्पादित करने के लिए बाध्य है. द निर्माण की गतिविधि में सभी गुण, तत्व और हैं कार्य अनुबंध की विशेषताएं हालांकि अनिवार्य रूप से यह एक हो सकती हैं फ्लैट की बिक्री का लेनदेन. इसे अलग तरीके से रखने के लिए, इसलिए निर्माण के रूप में लंबे समय तक अधिनियम के तहत.

(पैरा 30)

आगे आयोजित, इसके लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए में बेचे गए माल पर कर की निरंतर लेवी अगर

1. एक कार्य अनुबंध होना चाहिए.
2. माल के निष्पादन में शामिल होना चाहिए था एक काम अनुबंध, और

3. उन सामानों की संपत्ति को एक तिहाई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए पार्टी या तो सामान के रूप में या किसी अन्य रूप में.

ये शर्तें एक भवन अनुबंध या किसी में पूरी होती हैं निर्माण करने का अनुबंध. एक फ्लैट बनाने के लिए एक अनुबंध में, जरूरी है इसमें शामिल वस्तुओं की बिक्री का एक तत्व होगा और इसलिए, निर्माण अनुबंध कार्य अनुबंध की प्रजातियां हैं. अभी भी आगे, ए अनुबंध जिसमें एक कार्य अनुबंध और एक हस्तांतरण दोनों शामिल हैं अचल संपत्ति, इस तरह के अनुबंध के अपने चरित्र से इनकार नहीं किया जाता है एक काम अनुबंध किया जा रहा है. के संविधान का अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) भारत ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां माल नहीं हो सकता है माल के रूप में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन कुछ अन्य में स्थानांतरित किया जा सकता है वह रूप जो अचल संपत्ति के रूप में भी हो सकता है. इसमें कोई शक नहीं, कर लगाने के लिए राज्य विधायिका में कोई विधायी क्षमता नहीं है की सूची II के प्रवेश 54 के तहत अचल संपत्ति का हस्तांतरण सातवीं अनुसूची. हालांकि, राज्यों को बिक्री कर लगाने का अधिकार है फ्लैट की बिक्री के एक समझौते में माल की बिक्री पर जो भी एक है माल की एक बिक्री का घटक.

(पैरा 31)

आगे आयोजित, एक बार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर काम के अनुबंध के तहत आते हैं उनके और फ्लैट क्रेता के बीच एक समझौते में प्रवेश करना एक फ्लैट का निर्माण और अंततः जमीन के अंश के साथ फ्लैट बेचने के लिए,

हम कर योग्य निर्धारण के लिए व्यापक सिद्धांतों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं ऐसे कार्यों के अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के हस्तांतरण से संबंधित कारोबार. जहां डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर / ठेकेदार या उप-ठेकेदार खाते की उचित पुस्तकों को बनाए रखता है, यह मूल्य होगा की पुस्तकों के अनुसार कार्य अनुबंध में शामिल माल लेखा. दूसरी ओर, जहां डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर / ठेकेदार / उप-ठेकेदार उचित खातों या को बनाए नहीं रखता है उसके द्वारा बनाए गए खातों को विश्वसनीयता के योग्य नहीं पाया जाता है, यह होगा राज्य विधानमंडल के लिए एक सूत्र निर्धारित करने की अनुमति दी जाए एक तय करके श्रम, सेवा और भूमि की लागत के लिए शुल्क निर्धारित करना कार्य अनुबंध का विशेष प्रतिशत और कटौती की अनुमति देना इस प्रकार के लिए काम के अनुबंध के मूल्य से निर्धारित राशि कार्यों के निष्पादन में शामिल माल के मूल्य का आकलन करना अनुबंध. कर योग्य घटना माल में संपत्ति का हस्तांतरण है एक कार्य अनुबंध के निष्पादन और उक्त हस्तांतरण में शामिल है ऐसे सामानों में संपत्ति तब होती है जब माल को शामिल किया जाता है काम करता है. माल का मूल्य जो उपायों का गठन कर सकता है कर की लेवी के लिए कार्यों में माल को शामिल करने के समय माल का मूल्य होना चाहिए. निर्माण की गतिविधि डेवलपर आदि द्वारा किया गया कार्य केवल अनुबंध से होगा मंच वह फ्लैट क्रेता के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करता है. तथापि विभिन्न प्रमुखों के तहत अनुमेय कटौती के तथ्यों पर निर्भर करेगा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रत्येक मामला. यह स्पष्ट किया गया है कि जहां फ्लैट के पूरा होने के बाद समझौता किया जाता है या इकाई, कार्य अनुबंध का कोई तत्व नहीं होगा, लेकिन एक स्थिति में, जहां निर्माण पूरा होने से पहले समझौता किया जाता है, यह एक कार्य अनुबंध होगा. यदि निर्माण के समय और जब तक निर्माण पूरा हो गया था, निर्माण के लिए कोई अनुबंध नहीं था फ्लैट क्रेता के साथ भवन, निर्माण में प्रयुक्त माल उस समय से बिल्डर द्वारा बेचा गया माना नहीं जा सकता है कोई खरीदार नहीं है, भले ही इमारत को बेचने का इरादा हो निर्माण का कोई परिणाम नहीं होगा. के लिए बनाया गया मूल्य जोड़ समझौते के बाद हस्तांतरित माल को फ्लैट के साथ दर्ज किया जाता है क्रेता को केवल राज्य सरकार द्वारा कर के लिए प्रभार्य बनाया जा सकता है. अनुच्छेद के तहत एक कार्य अनुबंध में माल तत्व की बिक्री पर कर लगाना 366 (29A) (b) अनुसूची VII की प्रविष्टि 54 सूची II के साथ पढ़ा गया माल के निगमन के बाद भी भारत का संविधान स्वीकार्य है प्रदान किए गए कर के समय माल के मूल्य को निर्देशित किया जाता है निगमन और अचल के हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए नहीं है संपत्ति. डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर से कोई कर नहीं लिया जा सकता है या कार्यों में शामिल माल के मूल्य के संबंध में ठेकेदार

243I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

फ्लैट क्रेता के साथ समझौते के बाद अनुबंध जिस पर उपठेकेदार पहले ही कर का भुगतान कर चुका है.

(पैरा 31)

आगे आयोजित, वैधता से संबंधित शिकायत भी उठाई गई थी निर्देशों का दिनांक 7.5.2013, 4.6.2013 और 10.2.2014 (अनुलग्नक पी -2) कोली). निर्देश सं. 952 / ST-1 दिनांक 7.5.2013 (अनुलग्नक P-2) प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी किया गया यह प्रदान करता है कि समझौते /अनुबंध की बिक्री के लिए संभावित खरीदारों के साथ डेवलपर्स द्वारा दर्ज किया गया निर्माण पूरा होने से पहले अपार्टमेंट / फ्लैट उक्त परिपत्र का धारा 4 कर और कटौती की माप से संबंधित है श्रम की ओर और अन्य आरोपों की तरह. परिपत्र दिनांक 4.6.2013 था बिल्डरों और डेवलपर्स पर आकलन करने के संबंध में जारी किया गया. में कानूनी स्थिति के बारे में यहां बताया गया है, इसमें कोई अवैधता नहीं है दिनांक 7.5.2013 और 4.6.2013 के परिपत्र जारी करना. तथापि, 10.2.2014 को जारी परिपत्र के तहत एकमुश्त कर से संबंधित है रचना कर योजना और विश्लेषण करते समय निपटा दिया गया है अधिनियम की धारा 9 और नियमों के नियम 49 के प्रावधान.

(पैरा 36)

आगे आयोजित किया गया अब हम नियम 25 का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं नियम. उक्त नियम श्रम के संबंध में बहिष्करण प्रदान करता है, सेवाओं और अन्य आरोपों की तरह और के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है भूमि के मूल्य का बहिष्करण. जहां भी डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर या उप-ठेकेदार जो एक काम में निर्माण कार्य करता है अनुबंध उचित खातों को बनाए रखता है, यह वास्तविक के आधार पर होगा संपत्ति में उपयोग किए गए माल के मूल्य के अलावा. नियमों के नियम 25 (2) में श्रम, सेवाओं के लिए शुल्क में कटौती का प्रावधान है और अन्य आरोपों की तरह और जहां वे एक डेवलपर आदि द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों से पता लगाने योग्य नहीं हैं, प्रतिशत दर उक्त नियम में दी गई तालिका में निर्धारित हैं. यह जरूरी है केवल कर के लिए तंत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक मूल्य जोड़ समझौते के बाद हस्तांतरित माल को फ्लैट के साथ दर्ज किया जाता है कटौती जो अचल संपत्ति के मूल्य से संबंधित है. द विधायिका ने मूल्य के बहिष्कार के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है काम के अनुबंध और इसकी विधि से अचल संपत्ति मूल्यांकन को नियम बनाने के अधिकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है लिखो.

(पैरा 41)

आगे आयोजित, राज्य ने एक हलफनामा दायर किया था 24.4.2014 को श्री बी.एल. गुप्ता, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा.

(पैरा 42)

आगे आयोजित, की अनुपस्थिति में हलफनामे में जोर कानून या नियम में कोई विशिष्ट प्रावधान इसे नहीं देगा प्रस्तुत करने में प्रतिवादी की कार्रवाई के रूप में वैधानिक स्वाद शपथ पत्र दिनांक 24.4.2014 अपेक्षित परीक्षण को पूरा नहीं करेगा नियमों में संशोधन जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है कानून के अनुसार. हालांकि यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार 24.4.2014 दायर हलफनामे से बाध्य रहेगी इस न्यायालय में इसके द्वारा.

(पैरा 43)

आगे आयोजित, यदि कानून के प्रावधान मांग रहे हैं माल के मूल्य के अलावा किसी भी राशि पर बिक्री कर चार्ज करें कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित, प्रावधान होगा अल्ट्रा वाइस भारत का संविधान. कर होना है के साथ बिक्री के लिए समझौते में प्रवेश करने की तारीख पर और उसके बाद माल में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य से अधिक नहीं के मूल्य पर गणना की गई कर सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से प्रदान किए जाने से वहां बनाया जाए माल में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य पर और उसके बाद ही शुल्क लिया जाता है खरीदारों के साथ बिक्री के लिए समझौते में प्रवेश करने की तारीख. योग्य टर्नओवर, आमतौर पर इसमें एक अवशेष धारा शामिल होना चाहिए कानून के जनादेश के साथ सहमति ताकि सभी स्थितियों को कवर किया जा सके परिकल्पना की जा सकती है.

(पैरा 46)

आगे आयोजित, उपरोक्त के मददेनजर, अनिवार्य रूप से, का मूल्य अचल संपत्ति और किसी भी अन्य चीज की तारीख से पहले किया गया बिक्री के समझौते में प्रवेश को समझौते के मूल्य से बाहर रखा जाना है। एक डेवलपर के मामले में एक कार्य अनुबंध में माल का मूल्य आदि जिसके आधार पर वैट लगाया जाता है, उसका मूल्य होगा काम के अनुबंध में शामिल होने के समय भी माल जहां माल में संपत्ति बाद में गुजरती है। इसके अलावा, वैट को निर्देशित किया जाना है निगमन के समय माल का मूल्य और अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नतीजतन, नियम 25 (2) नियमों को इंगित की गई सीमा तक पढ़कर मान्य किया जाता है इसके अलावा और राज्य सरकार के अधीन शेष है इसका हलफनामा दिनांक 24.4.2014 है। राज्य सरकार लाएगी

2451.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

उपरोक्त के साथ नियमों की असंगति में आवश्यक परिवर्तन टिप्पणियों।

(पैरा 47)

आगे आयोजित, की धारा 42 के उप-धारा (1) के तहत अधिनियम, जहां कार्य ठेकेदार को निर्माण कार्य निष्पादित किया जाता है एक उप-ठेकेदार के माध्यम से, चाहे पूरे या आंशिक रूप से, यह होगा ठेकेदार और उप-ठेकेदार की संयुक्त और कई देयताएं। उपधारा 42 की धारा (2) स्पष्ट करती है कि एक ठेकेदार नहीं होगा ) एक उप-ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया है और उसका मूल्यांकन किया गया है अंतिम बनें। यह प्रावधान केवल राजस्व के हित को सुरक्षित करता है उप ठेकेदार की ओर से विफलता की स्थिति में उसका निर्वहन करने के लिए उप ठेकेदार द्वारा दर्ज लेनदेन के संबंध में कर की देयता ठेकेदार के साथ। इस प्रकार, प्रावधान को मनमाना नहीं कहा जा सकता है, किसी भी तरीके से भेदभावपूर्ण या अनुचित। का विवाद इस ओर याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील, इस प्रकार, निरस्त कर दिया गया है।

(पैरा 49)

आगे आयोजित, समान रूप से, धारा 9 की वैधता को चुनौती 2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7720 में नियमों के अधिनियम और नियम 49 (एम / एस) एबीडब्ल्यू सनसिटी वी. हरियाणा राज्य) को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियम 49 का अधिनियम के नियम और धारा 9 एकमुश्त कर की योजना प्रदान करते हैं रचना कर योजना के तहत जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से वैकल्पिक है। द डीलर इस योजना की सदस्यता के लिए किसी भी बाध्य कर्तव्य के तहत नहीं है। 1973 के अधिनियम के तहत इसी तरह के प्रावधान को डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था इस न्यायालय में तिरथ राम अहुजा वी. हरियाणा राज्य (1991) 83 एसटीसी 523. अधिनियम की धारा 9 नियमों के नियम 49 और परिपत्र के साथ पढ़ी जाती है दिनांक 10.2.2014 रचना के तहत कर के निर्धारण के लिए प्रदान करते हैं योजना जो वैकल्पिक है और इसके लिए चार्जिंग प्रावधान नहीं हैं वैट का लेवी। एक बार एक डीलर रचना योजना के लिए विरोध करता है जो है वैकल्पिक, उसे विभिन्न लाभ और विशेषाधिकार मिलते हैं जो अन्यथा हैं साधारण वैट डीलरों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, के मददेनजर में एपेक्स कोर्ट का फैसला कुथट्टुकुलम लिगस वी. उप बिक्री कर के आयुक्त (2014) 72 वीएसटी 353, की विधि इन प्रावधानों के तहत कर देयता का निर्धारण करने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है ऐसे डीलर द्वारा। उपरोक्त के मददेनजर, परिपत्र दिनांक 10.2.2014 नहीं हो सकता दोषपूर्ण हो।

(पैरा 50)

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

पुनीत अग्रवाल, एडवोकेट,

संदीप गोयल, एडवोकेट,

ऋषभ सिंगला, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए (2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5730 और 7575 में)।

मानव बजाज, के लिए वकील

सुमित गोएल, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए (2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6845 में).

राजीव अग्निहोत्री, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए (सीडब्ल्यूपी में 7440, 7441 और 2014 के 7614).

गजेंद्र महेश्वरी, एडवोकेट और  
पुनीत सिद्धार्थ, याचिकाकर्ता के लिए वकील

(सीडब्ल्यूपी में 7720, 8338, 8339, 12387 और 2014 के 12429).

भूपेश्वर जसवाल, के लिए वकील

मुकुल अग्रवाल, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए (2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7832 में).

अश्वानी चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज गुप्ता, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए  
(2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7834 में).

शम्मी कपूर, एडवोकेट और

मेघा सूरी, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए (2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7908 में).

राजेश गोयल, के लिए वकील

प्रितम सई, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए (2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8093 में).

अमर प्रताप सिंह, एडवोकेट और

अमरिंदर सिंह, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए (रौं)

(सीडब्ल्यूपी नं। 9314, 9364, 9370, 9456, 11072, 110911 और 2014 का 13684).

संजय सिंह, के लिए वकील

करणवीर सिंह खीर, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए (2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11696 में).

विक्रम जीत सिंह, के लिए वकील अमन पाल, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए  
(2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12170 में).

तनिष्क पेशावरिया, डीएजी, हरियाणा के साथ एम.के. दत्ता, हरियाणा राज्य के लिए  
वकील.

247LLR. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल

(1) यह आदेश 65 याचिकाओं के एक समूह का निपटान करेगा सीडब्ल्यूपी नोस. 5730, 5731, 5746, 5751, 5753, 5754, 5755, 6043, 6044,

6050, 6051, 6119, 6132, 6135, 6142, 6143, 6148, 6149, 6165, 6199,

6224, 6250, 6363, 6845, 7138, 7440, 7441, 7575, 7614, 7720, 7832,

7833, 7834, 7908, 8093, 8338, 8339, 9314, 9342, 9364, 9370, 9456,  
 9748, 10027, 10029, 10030, 10342, 10404, 10405, 10408, 10409,  
 10411, 10412, 10413, 10422, 11072, 11091, 11696, 12107, 12387,  
 12429, 12667, 13684, 2014 के 18075 और 2015 के 5120 के अनुसार

पार्टियों के लिए सीखा वकील, इसमें शामिल मुद्दे समान हैं। संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को 2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5730 से निकाला जा रहा है।

2. के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस रिट याचिका में भारत के संविधान, याचिकाकर्ता ने एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की है मंडमस की प्रकृति स्पष्टीकरण (i) की धारा 2 (1) (zg) की घोषणा करती है 25 (2) हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (इसके बाद) विशेष रूप से और अन्य में अब तक संबंधित प्रावधानों में वे भूमि के मूल्य को शामिल करते हैं अल्ट्रा वाइस भारत का संविधान अब तक अनुच्छेद 246 का उल्लंघन करता है भारत के संविधान की अनुसूची VII, सूची II, प्रविष्टि 54 के साथ पढ़ा गया; नोटिस जारी करने के लिए सर्टिफिकेट की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए (अनुलग्नक पी -3 कोली) पर कर लगाने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जारी किया गया फ्लैट / अपार्टमेंट / इकाइयों की बिक्री और वैट का आकलन करने के लिए; के लिए 4.6.2013 और 10.2.2014 (अनुलग्नक पी -2 कोली) के परिपत्रों को रद्द करना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है और जारी करने के लिए मंडमस के एक रिट के लिए प्रतिवादी नंबर 4 को चार्ज करने और करने के लिए नहीं पहले से भुगतान किए गए कर को वापस कर दें क्योंकि यह मूल्य से संबंधित है वैट के लिए मांगी जाने वाली सामग्री। इसके अलावा, कुछ रिट याचिकाओं में, मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश जबकि अन्य में रिट याचिकाएं, संशोधन प्राधिकरण द्वारा पारित संशोधन आदेश परिपत्रों और पूर्वोक्त प्रावधानों के आधार पर भी हमला किया गया है। कुछ मामलों में, नियमों के नियम 49 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 42 और धारा 9 की वैधता को भी चुनौती दी गई है।
3. संक्षेप में कहा गया है, के स्थगन के लिए आवश्यक तथ्य तत्काल रिट याचिका के रूप में वर्णित पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता विकास और बिक्री के व्यवसाय में लगे एक डेवलपर है अपार्टमेंट / फ्लैट / इकाइयाँ। इच्छुक खरीदार एक फ्लैट खरीदारों में प्रवेश करते हैं समझौता। संपत्ति को अंततः बिक्री विलेख के निष्पादन द्वारा बेचा जाता है कुल विचार पर स्टॉप शुल्क का भुगतान। एक परिपत्र दिनांक 7.5.2013 आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा जारी किया गया था, हरियाणा बताते हुए इसमें डेवलपर्स की बिक्री के लिए समझौतों में प्रवेश किया गया है निर्माण से पहले या दौरान निर्मित अपार्टमेंट या फ्लैट थे वैट के लिए प्रभार्य। नतीजतन, एक परिपत्र दिनांक 4.6.2013 जारी किया गया था बिल्डरों और डेवलपर्स पर आकलन करने के बारे में। इसके बाद, 10.2.2014 दिनांकित परिपत्र, 7.5.2013 दिनांकित परिपत्र विविध था और भूमि के मूल्य को शामिल करने की मांग की गई थी वैट लगाना। पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस (अनुलग्नक पी -3 कोली) वर्ष 2010-11 के लिए अधिनियम की धारा 17 के तहत जारी किए गए थे फ्लैट, फर्श और विला की बिक्री के लेनदेन पर कर लगाना

42,98,90,718 / - की राशि का आकलन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता

उक्त नोटिसों के लिए उत्तर (अनुलग्नक पी -4) दायर किया। हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं इस संबंध में प्राप्त किया गया था। डेवलपर की बिक्री में लगे हुए हैं अचल संपत्ति जहां स्टॉप शुल्क का भुगतान किया गया था और वहां भी कोई नहीं था कर की गणना के लिए अधिनियम के तहत प्रदान किया गया तंत्र अधिकारियों द्वारा जोर दिया गया कर लगाना असंवैधानिक था और अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से परे। इसलिए, वर्तमान रिट याचिकाओं/नोटिस पर, उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 ने रिट का चुनाव किया लिखित बयान दर्ज करके याचिकाएँ। उसमें यह निवेदन किया गया था कि बिल्डरों पर वैट की प्रयोज्यता और लेवी के बारे में मददा और भवन, फ्लैट और के निर्माण की गतिविधियों में लगे डेवलपर्स वाणिज्यिक संपत्तियों और संभावित खरीदारों को समान बिक्री याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे पहले ही एपेक्स कोर्ट ने सुलझा लिया है

एम / एस लार्सन एंड टूब्रो सीमित बनाम कर्नाटक राज्य<sup>3</sup> जिसमें यह आयोजित किया गया था कि बिल्डरों और डेवलपर्स आदि की गतिविधियों में लगे हुए हैं भवन, फ्लैट और वाणिज्यिक संपत्तियों का निर्माण कवर किया गया राज्य। अधिनियम में निहित 'कार्य अनुबंध' की परिभाषा है कर्नाटक के वैट अधिनियम के समान। याचिकाकर्ता-एम / एस सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड भी एक बिल्डर / डेवलपर / प्रमोटर है जो था आवासीय / वाणिज्यिक संपत्तियों के विकास में लगे। याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा इसके साथ कई तरह के समझौते किए गए फ्लैट / अपार्टमेंट / विला के निर्माण और बिक्री के लिए संभावित खरीदार/ मूल्यवान विचार के खिलाफ वाणिज्यिक परियोजनाएं। इसलिए, गतिविधि अभिव्यक्ति 'कार्य अनुबंध' की परिभाषा द्वारा कवर किया गया था अधिनियम की धारा 2 (1) (zt) में निहित है। इसके अलावा, 'बिक्री' की परिभाषा<sup>4</sup> जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (1) के धारा (ze) में निहित है 'कार्य अनुबंध' की गतिविधियाँ जो वैट अधिनियम के समान है

अधिनियम की धारा 2 के उप-धारा (1) में भी गतिविधियों को शामिल किया गया है 'अनुबंध काम करता है' जो इसके तहत पढ़ता है: -

<sup>3</sup> उप-धारा (ii) धारा (ze) का अर्थ है संपत्ति का हस्तांतरण माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में शामिल हो

(4) उपरोक्त और कानून को देखते हुए एम / एस लार्सन में और & टूब्रो लिमिटेड का मामला (सुप्रा), उत्तरदाताओं को संतोष था कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम के तहत वैट के भुगतान के लिए देयता लगाई है और तदनुसार, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है आवश्यक विवरण के तहत उन्हें सही कर देयता की मात्रा निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम। यह आगे कहा गया कि उत्तरदाताओं ने पहल की है वास्तविक कर निर्धारित करने के लिए अधिनियम के तहत मूल्यांकन कार्यवाही याचिकाकर्ताओं का दायित्व और उचित अवसर प्रदान किया था मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधित्व करने के लिए सुना जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के पास पारित आदेश को चुनौती देने का उपाय है अधिनियम। इसके अलावा, इस न्यायालय ने 19.1.2012 को सीडब्ल्यूपी नं. 2011 के 16751 /2013 (57 वीएसटी 453) के रूप में रिपोर्ट किया गया। ने याचिकाकर्ता को हटा दिया मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के पास इससे पहले। उत्तरदाताओं को अच्छी तरह से पता है कि भूमि की बिक्री नहीं थी अधिनियम के तहत कर योग्य अचल माल है, केवल के लिए नोटिस जारी किया में शामिल कर के लिए उत्तरदायी माल की बिक्री पर कर देयता की गणना अधिनियम के तहत कार्य अनुबंध का निष्पादन और कोई नोटिस का प्रस्ताव नहीं उनके द्वारा भूमि के मूल्य पर कर की लेवी जारी की गई है। के अनुसार उत्तरदाताओं, परिपत्र दिनांक 7.5.2013 (अनुलग्नक पी -2), दिनांकित 4.6.2013 और दिनांक 10.2.2014 प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी किए गए थे जो काम करने वाले ठेकेदारों और डेवलपर्स / बिल्डरों से संबंधित है ताकि निर्धारण में विभागीय अधिकारियों के बीच कुछ भ्रम को दूर किया जा सके सकल कारोबार और कटौती स्वीकार्य है और विचार जो कर के लिए उत्तरदायी था। किसी भी तरह से उक्त परिपत्र हस्तक्षेप नहीं करते हैं मूल्यांकन अधिकारियों के अर्ध न्यायिक कार्य। यह आगे था अनुरोध किया कि उक्त निष्पादन में माल का हस्तांतरण हो अनुबंध और हस्तांतरण में भुगतान किए जाने वाले विचार के लिए है चरणों। माल में संपत्ति का ऐसा हस्तांतरण धारा (zt) के अंतर्गत आता था अधिनियम की धारा 2 के उप-धारा (1)। इसलिए, याचिकाकर्ता ठेकेदार था और संभावित खरीदार एक अनुबंधकर्ता था। अन्य औसत रिट याचिकाओं में किए गए इनकार और बर्खास्तगी के लिए प्रार्थना की गई थी वही बनाया गया था।

(5) याचिकाकर्ताओं के लिए वकील ने कहा कि बिल्डरों / डेवलपर्स काम के ठेकेदार नहीं थे क्योंकि वे लगे हुए थे अचल संपत्ति की बिक्री। यह तर्क दिया गया था कि के प्रावधान अधिनियम की धारा 2 (1) (zg) और अधिनियम के नियम 25 (2) के लिए स्पष्टीकरण (i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम थे अल्ट्रा वायर्स का संविधान संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 54 सूची II के तहत भारत भारत में, राज्य को संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाने का अधिकार था माल के अनुबंध के निष्पादन में माल जबकि इसकी आड़ में, वे उस मूल्य पर कर वसूलना चाहते हैं जो मूल्य से अधिक था काम के अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित माल अचल संपत्ति के मूल्य और साथ असंबंधित खर्च सहित माल में संपत्ति का हस्तांतरण। यह अगली बार प्रस्तुत किया गया था कि यह अच्छी तरह से है तय किया कि सभी तत्व जिन पर राज्य विधानमंडल नहीं था वैट या बिक्री-कर लगाने की शक्ति को विशेष रूप से बाहर रखा जाना चाहिए एक्सप्रेस और विशिष्ट प्रावधानों का तरीका और यदि कोई तत्व है अनिर्दिष्ट रहें, प्रावधान होंगे अल्ट्रा वायर्स संविधान। संदर्भ यूपी की धारा 2 (विज्ञापन) में बिक्री मूल्य की परिभाषा के लिए बनाया गया था वैट अधिनियम, 2008 जो श्रम, सेवाओं के लिए शुल्क में कटौती की अनुमति देता है और अन्य निर्धारित राशियाँ जबकि नियम 9 के नियम में माल की बिक्री के कारोबार के निर्धारण से संबंधित है कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल जहां कटौती लागत का प्रतिनिधित्व करने वाली भूमि और राशि की आनुपातिक राशि स्थापना और अन्य समान खर्चों के लिए प्रदान किया जाता है। समर्थन दिल्ली वैट नियम, 2005 के नियम 3 से भी एकत्र किया गया था लागत के प्रति शुल्क को छोड़कर कर कार्य अनुबंध के लिए प्रदान करता है भूमि और अन्य खर्चों को नियम 3 के उप-नियम 3 में विस्तृत रूप से संदर्भित किया गया है। यह आग्रह किया गया था कि जब राज्य के पास कर लगाने की कोई शक्ति नहीं थी माल में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य के अलावा कुछ भी, अपने आप से प्रवेश, अधिनियम और नियमों के तहत प्रावधान वास्तव में अग्रणी थे अचल संपत्ति में मूल्य जोड़ को शामिल करने के लिए जबकि में सुप्रीम कोर्ट *M / s लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड* का मामला (सुप्रा) माना था कि राज्य के पास केवल मूल्य पर कर लगाने की शक्ति थी माल में परिवर्धन, संपत्ति जिसमें प्रवेश करने के बाद स्थानांतरित हो जाता है खरीदार के साथ समझौता। यह आगे कहा गया कि जब 'कार्य अनुबंध' की परिभाषा को 'बिक्री' की परिभाषा के साथ पढ़ा जाना था मूल्य, यह स्पष्ट था कि मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना था शुद्ध और सरल काम ठेकेदारों और डेवलपर्स नहीं। यहां तक कि कोई कर भी नहीं कर सकता सीधे हस्तांतरित सामग्री के संबंध में डेवलपर पर शुल्क लिया जाए उप-ठेकेदार द्वारा अधिनियम की धारा 42 के रूप में कर लगाने का प्रावधान है डेवलपर पर केवल उन मामलों में जहां संपत्ति द्वारा स्थानांतरित किया गया था उप-ठेकेदार जो अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। इसके अलावा, अनुभाग

2511.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

अधिनियम के 42 में ठेकेदार के संयुक्त और कई दायित्व निर्धारित हैं और कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल उप-ठेकेदार। अनुभाग अधिनियम के 42 (2) में यह प्रावधान है कि यदि मुख्य ठेकेदार साबित होता है आकलन करने वाले प्राधिकरण की संतुष्टि कि कर का भुगतान किया गया है उप-ठेकेदार और इस तरह के कर का आकलन अंतिम हो गया है, फिर वह ऐसे मामलों की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सीखा वकील के अनुसार, ठेकेदार और उप-ठेकेदार के लिए कर लगाना एक ही बिक्री दोहरे कर की राशि है और दो समझा नहीं जा सकता है एक काम अनुबंध में बिक्री। यह आग्रह किया गया था कि की गतिविधि डेवलपर द्वारा किया गया निर्माण केवल एक कार्य होगा मंच से अनुबंध जब डेवलपर के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करता है फ्लैट खरीदार। द्वारा हस्तांतरित माल के लिए किए गए मूल्य जोड़ डेवलपर, फ्लैट के साथ समझौते में प्रवेश करने के बाद क्रेता, एकमात्र घटक है जिसे कर द्वारा प्रभार्य बनाया जा सकता है अधिनियम के तहत राज्य। अंत में, विकल्प में, वकील सीखा प्रस्तुत किया गया है कि यदि हस्तांतरण के तत्व पर वैट लगाया जाता है समय अनुबंध में अचल संपत्ति इसे भीतर लाकर 'अनुबंध का काम करता है' शब्द का दायरा, फिर उस सीमा तक लेन-देन होना चाहिए के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संपत्ति संप्रेषण से नहीं गुजरती है लेकिन उस समझौते से जिसके लिए एक समझौता माना जाता था निर्माण। इसलिए, स्टांप ड्यूटी का इलाज नहीं किया जा सकता है लेन-देन के रूप में लेन-देन और स्टांप शुल्क, यदि कोई हो, तिथि तक भुगतान किया जाता है, वापसी योग्य हो जाता है। अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर वैट और स्टांप शुल्क की लेवी दोहरे कराधान की राशि है। कुछ रिट याचिकाओं में, अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों की वैधता पढ़ी गई है नियमों के नियम 49 के साथ भी पूछताछ की गई है।

(6) दूसरी ओर, राज्य के वकील ने प्रारंभिक तनाव सीखा की याचिका पर रिट याचिका की स्थिरता के बारे में आपत्ति वैकल्पिक उपाय में निर्णय से समर्थन प्राप्त किया राज्य का हरियाणा और अन्य बनाम एम / एस अल्फा



सर्जिकल पी. लिमिटेड.<sup>2</sup>, आयुक्त आयकर, गुजरात बनाम विजयभाई एन चंद्रानी<sup>3</sup>, एम/एस अल्काटेल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियांड राज्य तथा लार्सन एंड टूब्रो सीमित बनाम हरियाणा राज्य और अन्य<sup>5</sup> के गूण को चुनौती देना याचिकाकर्ताओं का दावा भी, यह आग्रह किया गया था कि विधि वैट लगाने के प्रयोजनों के लिए भूमि के मूल्य की गणना राज्य द्वारा पूरी तरह से निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप था

एपेक्स कोर्ट लार्सन एंड टूब्रो और रहजा बिल्डर्स के मामलों (सुप्रा) में. यह आगे कहा गया कि अधिनियम जो पूर्ण रूप से है प्रविष्टि 54, सूची II, सातवीं अनुसूची के साथ सहमति संविधान, माल पर कर लगाने का प्रावधान करता है जो अभिव्यक्ति करता है अचल संपत्ति शामिल नहीं है. इसके अलावा, राज्य ने एक सुसज्जित किया था हलफनामे में विशेष रूप से कहा गया है कि कर भूमि का कोई प्रस्ताव नहीं था डेवलपर्स / बिल्डरों के मामले में घटक. यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधान, जिनकी वैधता है याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी, कानून के अनुरूप थे.

(7) हमने पार्टियों के लिए सीखा हुआ परामर्श सुना है.

(8) पार्टियों के लिए सीखे गए वकील की सामग्री को देखते हुए हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्राथमिक मुद्दे उभर रहे हैं: -

1. डेवलपर्स और बिल्डर काम करते हैं या नहीं ठेकेदारों और समझौता के बीच डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर और संभावित खरीदार एक फ्लैट का निर्माण और उसके बाद कुछ के साथ एक ही बेचते हैं भूमि का हिस्सा, राज्य को वैट लगाने के लिए अधिकृत करता है उस पर?
2. यदि पहले मुद्दे का उत्तर सकारात्मक है, क्या इस तरह वैट के मूल्यांकन की विधि समझौते, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, के मूल्य को शामिल कर सकते हैं कर योग्य की गणना की विधि का पालन करके भूमि आयुक्त द्वारा व्यक्त तरीके से कारोबार परिपत्र दिनांक 7.5.2013, 4.6.2013 और 10.2.2014 और भी अधिनियम की धारा 2 (1) (zg) के लिए स्पष्टीकरण (i) की शर्तें और नियमों के नियम 25 (2)?

(iii) क्या अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान हैं और भी नियमों के नियम 49 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 होगी कानूनी और वैध होने के योग्य?

(iv) क्या अपील आदि का वैकल्पिक उपाय होगा वर्तमान रिट याचिकाओं का मनोरंजन करने के लिए इस न्यायालय को डीबार करें?

(9) पहले मुद्दे पर ध्यान देना, जरूरी है कि निम्नलिखित का संदर्भ दिया जाए: -

1. वैधानिक प्रावधान
2. 'कार्यों की कर क्षमता से संबंधित विधायी इतिहास अनुबंध 'और संवैधानिक प्रावधान.

10. 253 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

याचिकाकर्ताओं के लिए सीखे गए वकील ने इस पर ध्यान आकर्षित किया अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के लिए न्यायालय। अधिनियम हरियाणा राज्य में लागू हुआ w.e.f. 1.4.2003. यह प्रत्येक पर वैट लगाने का उद्देश्य रखता है मंच. एक डीलर अब भुगतान किए गए कर में कटौती के बाद कर का भुगतान करेगा बिक्री पर उसके द्वारा एकत्र किए गए कर से एक चौथाई के दौरान की गई खरीद उस तिमाही के दौरान माल की. अधिनियम की धारा 2 विभिन्न शर्तों को परिभाषित करती है जिसमें उल्लेख मिलता है. अधिनियम की धारा 2 (1) (zg) के अनुसार,<sup>3</sup>

किसी भी सामान की बिक्री, नकदी के रूप में बिक्री के समय किसी भी राशि की अनुमति नहीं है या अभ्यास के अनुसार व्यापार छूट, सामान्य रूप से प्रचलित है व्यापार, लेकिन डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किए गए किसी भी राशि के लिए किसी भी राशि का समावेश

स्पष्टीकरण (i) में जोड़ा गया है, जो हल करने के लिए सामग्री है इसमें शामिल विवाद, के हस्तांतरण के संबंध में प्रदान करता है माल में संपत्ति (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में शामिल हो एक कार्य अनुबंध का निष्पादन, बिक्री मूल्य का मतलब ऐसी राशि होगी जो है भुगतान किए गए मूल्यवान विचार की राशि से कटौती करके पहुंचे या ऐसे कार्यों के अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति को देय ऐसे के लिए श्रम और अन्य सेवा शुल्क का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि निष्पादन, और जहां ऐसे श्रम और अन्य सेवा शुल्क नहीं हैं मात्रात्मक, ऐसे शुल्कों की राशि की गणना इस तरह की जाएगी प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है।

10. इसका मतलब है कि सकल कारोबार का वह हिस्सा जो बनाने के बाद बचा है धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार कटौती; उप-धारा (3) के तहत कर के लिए उत्तरदायी माल की खरीद मूल्य धारा 3.
11. नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य के लिए बाहर ले जाने के लिए कोई समझौता मूल्यवान विचार, संयोजन, निर्माण, भवन, परिवर्तन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, स्थापना, फिटिंग बाहर, किसी भी चल या अचल की सुधार, मरम्मत या कमीशन संपत्ति.

<sup>3</sup> \* मूर्त या अमूर्त, समाचार पत्रों के अलावा, कार्रवाई योग्य दावे, पैसा, स्टॉक और शेयर या प्रतिभूतियां लेकिन इसमें शामिल हैं बढ़ती फसलों, घास, पेड़ों और चीजों से जुड़ी या

*CUD डेवलपर लिमिटेड, KARNAL v. हरियाणा और 254 की स्थिति OTHERS (अजय कुमार मित्तल, जे।)*

भूमि का वह हिस्सा बनाना जिसे अलग करने पर सहमति हो निम्नलिखित शब्दों में अधिनियम:

प्राप्त या प्राप्य बिक्री मूल्य का कुल मतलब है बेचे गए किसी भी सामान के संबंध में, चाहे वह प्रिंसिपल, एजेंट या हो किसी भी अन्य क्षमता में, ऐसे डीलर द्वारा और इसमें राज्य से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य शामिल है या अन्यथा का निपटान किया गया है बिक्री से;

स्पष्टीकरण। (i) सम्मान में माल की कीमतों का कुल आगे के अनुबंधों के लेनदेन, जिसमें माल वास्तव में वितरित नहीं किया जाता है, को सकल में शामिल नहीं किया जाएगा कारोबार.

2. प्राप्त या प्राप्य या भुगतान या देय पर कोई राशि मूल्य में भिन्नता, वृद्धि या डी-एस्केलेशन का खाता किसी भी व्यक्ति को पहले बेचा गया कोई भी सामान लेकिन बिल्कुल नहीं उस समय निर्धारित, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, में शामिल किया जा सकता है, या से बाहर रखा गया है, सकल कारोबार, जैसा भी मामला हो, में हो सकता है निर्धारित तरीके.
3. डीलर द्वारा कर के माध्यम से एकत्र की गई कोई भी राशि सकल कारोबार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और जहां कोई कर नहीं है अलग से चार्ज किया गया दिखाया गया है, इसे बाहर रखा जाएगा निम्न सूत्र ±

$$\text{कर} = \frac{\text{आर एक्स टीटीओ}}{100 + \text{आर}}$$

चित्रण ± यदि *TTO 220* है और *r 10* (प्रतिशत) है, तो कर होगा

*LLL*

(13) अधिनियम की धारा 3 का संबंध 'कर की घटना' से है जो इस प्रकार है इस प्रकार है: -

"3. (१) हर डीलर जो निरंतर बना रहेगा 1973 के इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी यह अधिनियम नहीं था लागू हो, और हर दूसरे डीलर जिसका सकल वर्ष के दौरान कारोबार तुरंत पूर्ववर्ती

2551.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

निर्धारित दिन परिभाषित या के रूप में कर योग्य क्वांटम से अधिक हो गया 1973 के अधिनियम में निर्दिष्ट, प्रावधानों के अधीन होगा उप-धारा (4), पर और से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो में उसके द्वारा प्रभावित माल की बिक्री पर नियुक्त दिन राज्य.

(2) और (3) XX XX XX

(4) उप-वर्गों (१), (२) और के तहत लगाया गया कर

(3) निर्धारित कर योग्य टर्नओवर पर गणना की जाएगी की दरों पर धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार धारा 7 के तहत लागू कर, और जहां कर योग्य है टर्नओवर कर की विभिन्न दरों पर कर योग्य है, कर की दर के प्रत्येक भाग के संबंध में अलग से लागू किया जाएगा कर की एक अलग दर के लिए उत्तरदायी कर योग्य कारोबार.

(5) से (7) XX XX; ; '

(14) संदर्भ अधिनियम की धारा ६ के लिए भी बनाया गया था कर योग्य कारोबार के निर्धारण के लिए प्रदान करता है. यह इस प्रकार पढ़ता है: -

IIIII

उप-धारा (2), में

प्रयोजनों के लिए एक डीलर के कर योग्य कारोबार का निर्धारण इस अधिनियम में, निम्नलिखित कटौती उसकी ओर से की जाएगी सकल कारोबार, अर्थात्: -

1. राज्य के बाहर माल की बिक्री का कारोबार;
2. अंतर-राज्य के दौरान माल की बिक्री का कारोबार व्यापार और वाणिज्य;
3. के आयात के दौरान माल की बिक्री का कारोबार क्षेत्र भारत में माल;
4. के निर्यात के दौरान माल की बिक्री का कारोबार भारत के क्षेत्र से बाहर का माल;
5. राज्य से बाहर माल के निर्यात का कारोबार;
6. बिक्री से अन्यथा माल के निपटान का कारोबार;
7. राज्य में छूट वाले सामानों की बिक्री का कारोबार;
8. ऐसे विदेशी राजनयिक को माल की बिक्री का कारोबार मिशन / वाणिज्य दूतावास और उनके राजनयिक, और एजेंसियां और संयुक्त राष्ट्र और उनके संगठन राजनयिकों को निर्धारित किया जा सकता है; तथा

(i) माल की बिक्री का कारोबार उसके पास लौट आया, जिसके अधीन इस तरह के प्रतिबंध और शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, और शेष को खरीद में जोड़ा जाएगा धारा 3 के उपधारा (3) के तहत कर योग्य, यदि कोई हो,

ध्यान दें। - 1. इस उप-धारा में

1. धारा (ए), (बी), (सी), (डी), (जी) और (एच) के उद्देश्य के लिए, माल की बिक्री की कीमतों का कुल जो हिस्सा है सकल कारोबार;
2. धारा (ई) और (एफ) के उद्देश्य के लिए, का कुल राज्य से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य या निपटान अन्यथा बिक्री से, जैसा कि मामला हो सकता है, जो का हिस्सा है सकल कारोबार; तथा
3. क्लॉज (i) के प्रयोजन के लिए, माल की बिक्री की कीमतों का कुल जो सकल कारोबार का हिस्सा है (1973 के अधिनियम के तहत सहित).

ध्यान दें। - २. यदि किसी सामान के संबंध में कारोबार शामिल है इस उप-धारा के किसी भी धारा के तहत कटौती में, यह होगा के किसी अन्य धारा के तहत कटौती का हिस्सा नहीं है उप-धारा.

2. उप-धारा (1) में उल्लिखित कटौती ऐसे में मूल्यांकन प्राधिकारी को प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य होगी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे दस्तावेज़ या ऐसे प्रमाण, जैसे तरीके निर्धारित किए जा सकते हैं.
3. अन्यथा उप-अनुभाग (1) में दिए गए अनुसार सहेजें प्रयोजनों के लिए एक डीलर के कर योग्य कारोबार का निर्धारण इस अधिनियम में, उसके सकल से कोई कटौती नहीं की जाएगी कारोबार.

(15) अधिनियम की धारा 9 में एकमुश्त कर के भुगतान से संबंधित है कर के बदले जो के रूप में पढ़ता है: -

"9. (1) राज्य सरकार, जनहित में और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकती है, जैसे कि वह फिट हो सकती है, स्वीकार कर सकती है डीलरों के किसी भी वर्ग से, इसके तहत देय कर के बदले में अधिनियम, किसी भी अवधि के लिए, रचना के माध्यम से, एकमुश्त उत्पादन क्षमता या कुछ अन्य उपयुक्त के साथ जुड़ा हुआ है व्यवसाय की सीमा की माप, या की एक फ्लैट दर पर गणना की जाती है व्यवसाय की सकल प्राप्तियां या खरीद का सकल कारोबार या बिक्री या इसी तरह के अन्य उपाय, किसी के साथ या बिना

2571.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली कटौती सरकार, और इस तरह की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा अंतराल और इस तरह से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य से हो सकती है डीलरों के ऐसे वर्ग का सम्मान, सरलीकृत प्रणाली निर्धारित करें पंजीकरण, खातों का रखरखाव और रिटर्न दाखिल करना जो इस तरह की अवधि के दौरान लागू रहेगा रचना.

2. कोई भी डीलर जिसके मामले में उप-धारा के तहत संरचना नहीं है (1) लागू है, उसके द्वारा माल की बिक्री के लिए एक कर चालान जारी करेगा और कोई भी डीलर जिसे ऐसे डीलर द्वारा बेचा जाता है के संबंध में इनपुट टैक्स के किसी भी दावे के हकदार होंगे उसे माल की बिक्री.
3. एक डीलर जिसके मामले में उप-धारा के तहत रचना होती है
1. बनाया गया है और इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है और शर्तें, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, एक आवेदन युक्त करके ऐसी रचना से बाहर निकलें निर्धारित तरीके से निर्धारित विवरण प्राधिकरण का आकलन करना, और यदि आवेदन क्रम में है, इस तरह की रचना की समाप्ति पर प्रभाव पड़ता है आवेदन करने के बाद ऐसी अवधि हो सकती है *SUAFileal3E1*

(16) अधिनियम की धारा 42 पर कर लगाने का प्रावधान है डेवलपर उन मामलों में भी जहां संपत्ति द्वारा स्थानांतरित किया गया था उप-ठेकेदार. उक्त अनुभाग इस प्रकार है: -

"42. संयुक्त और के कुछ दिनों के कई दायित्व डीलरों (1) जहां एक काम ठेकेदार एक उप नियुक्त करता है ठेकेदार, जो काम के अनुबंध को निष्पादित करता है, चाहे वह अंदर हो पूरे या आंशिक रूप से, ठेकेदार और उपठेकेदार करेगा के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी दोनों हो माल में संपत्ति का हस्तांतरण चाहे माल के रूप में या कुछ में कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल अन्य रूप उप-ठेकेदार द्वारा.

2. यदि ठेकेदार की संतुष्टि के लिए साबित होता है प्राधिकरण का आकलन करना कि कर का भुगतान उप द्वारा किया गया है निष्पादन में शामिल माल की बिक्री पर ठेकेदार उपठेकेदार और अनुबंध द्वारा काम करता है इस तरह के कर का आकलन अंतिम हो गया है, ठेकेदार करेगा ऐसे सामानों की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है लेकिन वह

इनपुट टैक्स का दावा करने का हकदार होगा, यदि कोई हो, तो उनके संबंध में यदि उप-ठेकेदार द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया है।

3. जहां एक एजेंट किसी भी सामान को खरीदता या बेचता है एक प्रिंसिपल, ऐसे एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होंगे के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी एजेंट द्वारा माल की खरीद या बिक्री।
4. यदि प्रिंसिपल जिसकी ओर से एजेंट ने खरीदा है या बेचा माल आकलन की संतुष्टि के लिए साबित होता है अधिकार है कि इस तरह के माल पर कर का भुगतान किया गया था एजेंट और इस तरह के कर का आकलन अंतिम हो गया है, फिर, प्रिंसिपल ऐसे सामानों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन वह इनपुट टैक्स का दावा करने का हकदार होगा, यदि कोई हो, के संबंध में। *NEP inialleP IIKINWVE-1-1WIEDISIRI LE Naurlyz*

(17) नियम 25 (2) और 49 के नियम भी संदर्भित थे याचिकाकर्ताओं के लिए वकील सीखा. नियम 25 (2) नियम प्रदान करता है एक काम ठेकेदार के लिए कर योग्य कारोबार की गणना करते समय किए जाने वाले कुछ बहिष्करणों के लिए: -

25. कर योग्य कारोबार की गणना। - (2) (क) के मामले में कार्य अनुबंध के निष्पादन से उत्पन्न होने वाला कारोबार या नौकरी का काम, कर योग्य कारोबार का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि श्रम, सेवाओं और अन्य जैसे आरोपों को बाहर करें डीलर के उचित रिकॉर्ड जैसे चालान, वाउचर, चालान या किसी अन्य दस्तावेज को बनाए रखने के अधीन शुल्क की संतुष्टि के लिए शुल्क का भुगतान करना कर प्राधिकरण.

ख. उप-नियम (2) के धारा (ए) के प्रयोजन के लिए, शुल्क कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम सेवाओं की ओर शामिल,

1. कार्यों के निष्पादन के लिए श्रम शुल्क;
2. योजना और संग्रह के लिए शुल्क
3. उपभोग्य सामग्रियों की लागत जैसे पानी, बिजली, ईंधन, आदि. कार्यों के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली संपत्ति को अनुबंधित करती है जो ए के निष्पादन के दौरान स्थानांतरित नहीं किया जाता है काम करता है अनुबंध;
4. ठेकेदार की स्थापना की लागत इस हद तक है श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए भरोसेमंद;
5. 259 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)  
अन्य समान खर्च श्रम की आपूर्ति के लिए निर्भर हैं सेवाएं;
6. ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ इस हद तक है के अधीन श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए भरोसेमंद कार्य साइटों के लाभ और हानि खाते की प्रस्तुत:

बशर्ते कि जहां श्रम के लिए शुल्क की राशि, डीलर या डीलर के खातों की पुस्तकों से सेवाओं और अन्य आरोपों का पता नहीं लगाया जा सकता है इस तरह के आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य का उत्पादन, ऐसे शुल्कों की राशि की गणना की जाएगी तालिका में निर्दिष्ट मूल्यवान विचार का प्रतिशत नीचे दिया गया:

तालिका

XX XXXX

(18) नियम नियमों के 49 के तहत एकमुश्त कर के साथ संबंधित है: -

"49. के संबंध में एकमुश्त योजना ठेकेदारों

(1) अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक ठेकेदार, में हो सकता है निष्पादन के लिए उसे दिए गए एक कार्य अनुबंध का सम्मान राज्य, संपत्ति के हस्तांतरण पर अधिनियम के तहत उसके

द्वारा देय कर के बदले में भुगतान करें (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य में प्रपत्र) अनुबंध के निष्पादन में शामिल, एक मुश्त राशि कुल मूल्यवान विचार के चार प्रतिशत पर गणना की गई अनुबंध के निष्पादन के लिए प्राप्य, एक बनाकर भीतर उचित मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए आवेदन अनुबंध के पुरस्कार के तीस दिन, जिसमें वह शामिल था निम्नलिखित विवरण:

1. आवेदक ठेकेदार का नाम:
2. टिन:

(पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करें, यदि पंजीकृत नहीं है या नहीं पंजीकरण के लिए आवेदन किया)

3. संविदा का नाम:
4. अनुबंध के पुरस्कार की तारीख;
5. अनुबंध के निष्पादन का स्थान:
6. अनुबंध की कुल लागत:
7. निष्पादन की अवधि:

और अनुबंध या इस तरह के हिस्से की एक प्रति संलग्न करना कुल लागत और भुगतान से संबंधित है.

2. आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे पंजीकरण के लिए एक आवेदन करें. की प्राप्ति पर आवेदन, मूल्यांकन प्राधिकरण संतोषजनक होने के बाद करेगा स्वयं उसे कि आवेदन की सामग्री सही है, उसी की अनुमति दें.
3. एकमुश्त ठेकेदार बनाने के लिए उत्तरदायी होगा एकमुश्त तिमाही का भुगतान चार प्रतिशत पर गणना की गई अनुबंध के निष्पादन के लिए तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्य भुगतान. गांठ का भुगतान गणना की गई राशि तीस दिनों के भीतर बनाई जाएगी उसमें कटौती के बाद तिमाही के करीब आने के बाद की ओर से अनुबंधकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि उस तिमाही के लिए धारा 24 के तहत ठेकेदार. राजकोषभुगतान के प्रमाण में रसीद और कर का प्रमाण पत्र संविदा से प्राप्त कटौती और भुगतान होगा त्रैमासिक रिटर्न से सुसज्जित हो.
4. एकमुश्त ठेकेदार तिमाही में रिटर्न दाखिल करेगा के बंद होने के एक महीने के भीतर फॉर्म वैट-आर 6 में अंतराल तिमाही और उसके कारण एकमुश्त, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद इस तरह के रिटर्न के अनुसार उप-नियम (4) के तहत.
5. एकमुश्त ठेकेदार बनाने का हकदार होगा दोनों के अनुबंध के निष्पादन में उपयोग के लिए माल की खरीद सेंट्रल फॉर्म सी में घोषणा के अधिकार पर भी उप-धारा के धारा (ए) के तहत निर्धारित वैट-डीआई (3) धारा 3 और इस प्रयोजन के लिए उसे एक माना जाएगा निर्माता.
6. एकमुश्त ठेकेदार पूरा बनाए रखेगा सेंट्रल फॉर्म सी और फॉर्म वैट में घोषणाओं का लेखा-जोखा DI उसके द्वारा उपयोग किया जाता है और, खरीदे गए माल का उपयोग इन रूपों के अधिकार पर. उसकी आवश्यकता होगी माल ले जाने के लिए फॉर्म डी 3 में घोषणा (ओं) का उपयोग करें जिसे वह ध्यान रखेगा. वह भी पूरा रखेगा अनुबंध के निष्पादन के लिए उसके द्वारा प्राप्य भुगतान, और वास्तव में उसके द्वारा प्राप्त भुगतान.
7. एकमुश्त ठेकेदार को एकमुश्त राशि का भुगतान करना होगा उसके बाद उसे दिए गए हर काम के अनुबंध का सम्मान

अनुबंध का पुरस्कार जिसके संबंध में उन्होंने पहली बार चुना था एकमुश्त भुगतान करें और वह कर के संबंध में कर का भुगतान करना जारी रखेगा इससे पहले कि वह एकमुश्त नहीं है, जैसे अनुबंध से सम्मानित किया गया ठेकेदार.

8. एकमुश्त ठेकेदार किसी भी समय दिखाई दे सकता है उपयुक्त मूल्यांकन प्राधिकरण से पहले या एक अधिकृत एजेंट एक्सप्रेस के माध्यम से एकमुश्त भुगतान की योजना से बाहर निकलने के अपने इरादे को लिखित रूप में व्यक्त करता है अधिनियम के तहत देय कर। उसके बाद दिए गए अनुबंधों के संबंध में ऐसा ठेकेदार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अधिनियम के तहत देय कर के बदले में एकमुश्त लेकिन सम्मान में अन्य अनुबंध (ओं) में वह एकमुश्त भुगतान करना जारी रखेगा इस तरह के प्रत्येक अनुबंध के पूरा होने तक अधिनियम के तहत देय कर का झूठ.
9. एकमुश्त ठेकेदार, जब एकमुश्त की दर हो सकती है संशोधित, एकमुश्त भुगतान की योजना से बाहर निकलने अधिनियम के तहत देय कर के बदले में पेश होने से पहले स्वयं या किसी के माध्यम से उचित मूल्यांकन प्राधिकरण ऐसे संशोधन के नब्बे दिनों के भीतर अधिकृत एजेंट और योजना से बाहर निकलने के अपने इरादे को लिखने में व्यक्त करना एकमुश्त भुगतान. ऐसे ठेकेदार के लिए उत्तरदायी होगा एकमुश्त में संशोधन से पहले की अवधि के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान करें संयुक्त राष्ट्र की संशोधित दर पर और के हस्तांतरण के संबंध में राशि दर किसी भी सामान में संपत्ति, चाहे सामान के रूप में या किसी अन्य में फॉर्म, अनुबंध के निष्पादन में शामिल होने के बाद, वह एक ठेकेदार के रूप में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि एक गांठ नहीं है।
19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ, विधायी इतिहास की सराहना करने के लिए 'कार्य अनुबंध' की कर क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
20. बिक्री कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रवेश 54 द्वारा राज्यों की विधानसभाएं. मूल रूप से लागू की गई प्रविष्टि
19. में एपेक्स कोर्ट के फैसले के बाद बंगाल की प्रतिरक्षा कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य<sup>6</sup> संसद ने संविधान पारित किया (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 जिसे स्वीकृति मिली

1955 एससीआर 379

11.9.1956 को राष्ट्रपति. उक्त संशोधन द्वारा, सूची I में प्रविष्टि 92-ए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में जोड़ा गया था निम्नलिखित शर्तें:

<sup>3</sup> के अलावा अन्य सामानों की बिक्री या खरीद पर *W-A. Taxes* समाचार पत्र, जहां इस तरह की बिक्री या खरीद होती है सूची II में मौजूदा प्रविष्टि 54 को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था: -

(22) यह सवाल कि क्या माल की लागत ए द्वारा आपूर्ति की जाती है भवन निर्माण के दौरान ठेकेदार का निर्माण हो सकता है बिक्री कर के भुगतान के अधीन होने के कारण एपेक्स कोर्ट द्वारा हल किया गया था मद्रास राज्य बनाम गैनन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. (मैड्रास) लिमिटेड जो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील थी गैनन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में मद्रास. (मैड्रास) लिमिटेड वी. का राज्य मद्रास. इस मामले में एपेक्स कोर्ट ने कहा कि इसकी सही व्याख्या पर अभिव्यक्ति "माल की बिक्री" का मतलब पार्टियों के बीच एक समझौता था बहुत माल की बिक्री के लिए जिसमें अंततः संपत्ति पारित हुई. एक भवन अनुबंध में जहां पार्टियों के बीच समझौता था कि ठेकेदार को विनिर्देशों के अनुसार भवन का निर्माण करना चाहिए समझौते में निहित है और विचार में प्राप्त किया है भुगतान के रूप में प्रदान किया गया था, न तो बेचने के लिए कोई अनुबंध था निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और न ही संपत्ति उसमें से गुजरी चल. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति "बिक्री माल" उस समय था जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 था अधिनियमित, सामान्य कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कानूनी आयात का एक शब्द माल की बिक्री से संबंधित और उससे संबंधित विधायी अभ्यास में

विषय और अनुसूची II की सूची II में प्रविष्टि 48 में व्याख्या की जानी चाहिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 के समान अर्थ है माल की बिक्री अधिनियम, 1930. यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक इमारत में अनुबंध जो एक, संपूर्ण और अविभाज्य था, उसकी कोई बिक्री नहीं थी माल और यह प्रांतीय की क्षमता के भीतर नहीं था की अनुसूची VII में सूची II में प्रविष्टि 48 के तहत विधानमंडल भारत सरकार अधिनियम, 1935, की आपूर्ति पर कर लगाने के लिए इस तरह के अनुबंध में प्रयुक्त सामग्री इसे बिक्री के रूप में मानती है. सर्वोच्च कोर्ट ने बाद के फैसलों में कहा था कि उक्त निर्णय हालांकि भारत सरकार में प्रावधानों के आधार पर प्रदान किया गया था

263I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

अधिनियम, 1935 समान रूप से प्रवेश 54 में पाए गए प्रावधानों पर लागू था संविधान की अनुसूची VII की सूची II. इस निर्णय के आधार पर, किसी कार्य के तहत प्राप्त राशियों पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है एक भवन ठेकेदार द्वारा अनुबंध, भले ही उसने इमारतों के निर्माण के लिए सामान की आपूर्ति की थी.

(23) वर्ष 1982 में संसद ने पारित किए 46<sup>वें</sup> संशोधन कई मामलों को लाने के लिए कई मामलों में संविधान में संशोधन लेनदेन, जिसमें माल में संपत्ति पारित हुई, लेकिन नहीं थी दायरे के भीतर बिक्री कर लगाने के उद्देश्य से बिक्री के रूप में माना जाता है बिक्री कर लगाने के लिए राज्यों की शक्ति. 46 वें संशोधन द्वारा ए नए धारा, अर्थात् धारा (29A) को अनुच्छेद 366 में पेश किया गया था संविधान. संविधान के अनुच्छेद 366 का धारा (29A) इस प्रकार है:

3

में में में  
इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ नहीं

अन्यथा आवश्यकता होती है, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में है इसका अर्थ क्रमशः उन्हें सौंपा गया है, यह कहना है-(29-ए) 'माल की बिक्री या खरीद पर कर' शामिल हैं<sup>2</sup>

1. स्थानांतरण पर एक कर, अन्यथा एक के अनुसरण में अनुबंध, नकदी के लिए किसी भी सामान में संपत्ति का, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार;
2. माल के हस्तांतरण पर एक कर (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) एक के निष्पादन में शामिल हो काम करता है अनुबंध;
3. किराया-खरीद या किसी पर माल की डिलीवरी पर एक कर किशतों द्वारा भुगतान की प्रणाली;
4. किसी भी सामान का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर एक कर। के लिये नकदी के लिए कोई भी उद्देश्य (निर्दिष्ट अवधि के लिए या नहीं), आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार;
5. किसी भी असंबद्ध द्वारा माल की आपूर्ति पर एक कर नकदी के लिए किसी सदस्य को व्यक्तियों का संघ या निकाय, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार;
6. आपूर्ति पर एक कर, के माध्यम से या भाग के रूप में। किसी भी सेवा का या किसी अन्य तरीके से, माल का, भोजन का या मानव उपभोग या किसी भी पेय के लिए कोई अन्य लेख (चाहे या न हो), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा है नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार के लिए, और इस तरह के हस्तांतरण, वितरण या किसी भी सामान की आपूर्ति होगी बनाने वाले व्यक्ति द्वारा उन सामानों की बिक्री माना जाता है

स्थानांतरण, वितरण या आपूर्ति और उन सामानों की खरीद द्वारा वह व्यक्ति जिसे इस तरह का स्थानांतरण, वितरण या आपूर्ति है

24. चालीस से पहले संशोधन समग्र अनुबंध, प्रविष्टि 54, अनुसूची II की सूची II के तहत राज्यों के बिक्री कर के लिए योग्य नहीं थे सातवीं. 46 वें संशोधन के बाद कार्य अनुबंध जो एक था अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी)



में बनाए गए एक कानूनी उपन्यास द्वारा अविभाज्य, था एक अनुबंध में बदल दिया गया जो माल की बिक्री के लिए एक में विभाजित था और श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अन्य. इस प्रकार, यह बन गया है राज्यों के लिए शामिल माल के मूल्य पर बिक्री कर लगाना संभव है एक कार्य अनुबंध में उसी तरह से जिसमें बिक्री कर लगाया गया था एक भवन अनुबंध में आपूर्ति की गई वस्तुओं और सामग्रियों की कीमत पर, जिन्हें दो अलग और अलग-अलग हिस्सों में दर्ज किया गया था.

25. आगे बढ़ने से पहले विश्लेषण करना आवश्यक होगा संविधान के अनुच्छेद 366 के धारा 29-ए के उप-धारा (बी). अनुच्छेद 366 संविधान का परिभाषा धारा है. यह प्रदान करता है कि में संविधान जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो, अभिव्यक्ति उस लेख में परिभाषित अर्थ क्रमशः उन्हें सौंपा गया है उस लेख में. अभिव्यक्ति 'माल' को धारा (12) में परिभाषित किया गया है सभी सामग्रियों, वस्तुओं सहित संविधान का अनुच्छेद 366 और लेख. क्लॉज (29-ए) के उप-धारा (बी) में कहा गया है कि 'माल की बिक्री या खरीद पर कर' में अन्य बातों के अलावा हस्तांतरण पर कर शामिल है माल में संपत्ति (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल. पर जोर दिया गया है माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में). किसी भी सामान के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति का उल्लेख करते हुए उप-धारा (ए) से (एफ) धारा (29-ए) के अनुसार होता है, बाद वाला भाग धारा (29-ए) यह निर्धारित करता है कि किसी भी तरह का 'हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति माल 'व्यक्ति द्वारा उन सामानों की बिक्री माना जाएगा स्थानांतरण, वितरण या आपूर्ति और उन सामानों की खरीद करना उस व्यक्ति द्वारा जिसे इस तरह का स्थानांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है. इसलिए, धारा (29-ए) के उप धारा (बी) के तहत माल में संपत्ति का हस्तांतरण, निष्पादन में शामिल माल की बिक्री माना जाता है स्थानांतरण और खरीद करने वाले व्यक्ति द्वारा एक कार्य अनुबंध उस व्यक्ति द्वारा उन सामानों को जिनके लिए ऐसा स्थानांतरण किया जाता है. द के अनुच्छेद 366 के धारा (29-ए) में नई परिभाषा की शुरुआत संविधान ने बिक्री या खरीद पर कर के दायरे को बढ़ा दिया था माल 'जहां भी संविधान में इसके भीतर शामिल किया गया माल के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की गुंजाइश हो सकती है उप-धारा (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन के तहत

265 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

जहां भी इस तरह के हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति बिक्री कर के अधीन हो जाती है. राज्य सूची के प्रवेश 54 में 'माल की बिक्री या खरीद पर कर' की अभिव्यक्ति, इसलिए, संपत्ति के हस्तांतरण पर एक कर शामिल है माल में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) एक कार्य अनुबंध का निष्पादन भी. उप के आधार पर कर लगाया जा सकता है-इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 366 के धारा (29-ए) का धारा (बी) उसी अनुशासन के अधीन हो जाता है जिसके तहत प्रवेश के तहत कोई भी लेवी राज्य सूची के 54 को संविधान के तहत बनाया गया है.

(26) के अनुच्छेद 366 (29ए) के प्रावधानों की व्याख्या करना भारत का संविधान, एपेक्स कोर्ट की संविधान बेंच बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम भारत का संघ<sup>8</sup> था के तहत नीचे रखा: -

<sup>39</sup> माल में संपत्ति का गुजरना जो कार्यों में शामिल है अनुबंध और धारा (29-ए) द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पना संविधान के अनुच्छेद 366 से सहमत होना मुश्किल है राज्यों का तर्क है कि जो गुण स्थानांतरित किए जाते हैं एक काम अनुबंध के निष्पादन में मालिक के लिए नहीं हैं माल अनुबंध के निष्पादन में शामिल है, लेकिन ए समूह, वह पूरी इमारत है जो वास्तव में है का निर्माण किया. 46 वें संशोधन के बाद यह संभव नहीं है राज्यों की दलील है कि क्या एक में स्थानांतरित किया जाता है काम करता है अनुबंध अचल संपत्ति में अधिकार है.

40. हम उन राज्यों के रवैये पर हैरान हैं जिनके पास है 46 वीं के पारित होने पर दलील को आगे रखा संविधान में संशोधन ने राज्यों को सम्मानित किया था राज्य सूची के प्रवेश 54 के तहत बिक्री-कर लगाने की उनकी शक्ति के संबंध में उनके पास पहले की तुलना में बड़ी स्वतंत्रता थी. द 46 वां

संशोधन इसके लिए संभव बनाने से अधिक नहीं है माल और सामग्री की कीमत पर बिक्री कर लगाने के लिए राज्य काम के अनुबंधों में उपयोग किया जाता है जैसे कि ऐसे सामानों की बिक्री होती है और सामग्री. हम उस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं जो उप-धारा(ख) अनुच्छेद 366 (2 ए) के बराबर पढ़ा जाना चाहिए सातवीं अनुसूची की सूची II में एक अलग प्रविष्टि राज्यों को बिक्री पर कर लगाने में सक्षम संविधान और प्रवेश 54 से स्वतंत्र खरीद. जैसा कि संविधान आज "डीम्ड" बिक्री सहित माल की बिक्री और खरीद पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति मौजूद है

<sup>8</sup> (1989) 2 एससीसी 645

और अनुच्छेद 366 के धारा (29 ए) के तहत माल की खरीद है केवल एंटी 54 में पाया जा सकता है और इसके बाहर नहीं. हम कर सकते हैं यहाँ संविधान बेंच की टिप्पणियों का पुनर्पूजीकरण करें का मामला बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि कई के ऑपरेटिव प्रावधान अनुच्छेद 286 के कुछ हिस्से जो लेवी पर प्रतिबंध लगाते हैं राज्यों द्वारा बिक्री कर अलग से निपटने का इरादा है विषयों और एक को दूसरे में अनुमानित या पढ़ा नहीं जा सकता है और किसी भी बिक्री या खरीद के दौरान उनमें से प्रत्येक का पालन करना पड़ता है राज्य सूची के प्रवेश 54 के तहत कर लगाया जाता है.

41. इसलिए, हम घोषणा करते हैं कि बिक्री कर कानून पारित हो गए हैं माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर लगाने वाले राज्यों के विधान (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) एक कार्य अनुबंध का निष्पादन प्रतिबंधों के अधीन है और प्रत्येक धारा या उप-धारा में उल्लिखित शर्तें संविधान का अनुच्छेद 286. हालाँकि, हम इसे स्पष्ट करते हैं हमारे द्वारा पहले और विचार किए गए मामले एक से संबंधित हैं 'काम के अनुबंध' की सामान्य अवधारणा का नमूना'. मामलापुस्तक अनंत किस्म के चित्रण से भरी है - जो भी हो सकता है व्यक्तिगत मामलों के स्थितिजन्य अंतर, राज्य की कर शक्ति पर संवैधानिक सीमाएं लागू हैं "में 'बिक्री पर कर या" की विस्तारित अवधारणा का संदर्भ माल की खरीद "अनुच्छेद के तहत संवैधानिक रूप से परिभाषित स्थितिजन्य संशोधनों के लिए.
42. अनुच्छेद 366 (29 ए) में संवैधानिक-संशोधन पढ़ा गया प्रासंगिक कराधान प्रविष्टियों के साथ राज्य को सक्षम करने में सक्षम है सामाजिक और आर्थिक के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में इसकी कर शक्ति समुदाय का जीवन. विशेष रूप से इस शक्ति को बढ़ाने में में शामिल माल में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में जैसा कि यह वंचितों की आवास परियोजनाओं को प्रभावित करता है और समाज के कमजोर वर्ग, राज्य शायद हो सकते हैं अपनी कराधान शक्ति को सामाजिक की परिधि में धकेलना उस शक्ति की सीमा और, शायद, संवैधानिक की भी असमान से निपटने में उस शक्ति की सीमा. के ऐसे वर्ग में मामले 'निर्माण गतिविधि' वास्तव में एक बुनियादी निर्वाह से संबंधित हैं जरूरत. यह राज्य के लिए बुद्धिमान और उपयुक्त होगा

267I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

विचार करें कि क्या अपेक्षित और उपयुक्त वर्गीकरण इस तरह के निर्माण गतिविधि परिचर के साथ नहीं बनाया जाना चाहिए उचित अलग उपचार के लिए ऐसे सामाजिक उद्देश्य

(27) पूर्वोक्त निर्णय को मंजूरी देते हुए, एक और संविधान बेंच में **Gannon Dunkerley** एंड कंपनी और अन्य बनाम राज्य का राजस्थान और अन्य के तहत निष्कर्ष निकाला था: -

<sup>349</sup> प्रस्तुत करने की स्थिति खर्चों को स्थापित करने के लिए आवश्यक सामग्री श्रम के लिए कटौती के पूर्वोक्त प्रमुखों के तहत किए गए और सेवाएं. लेकिन ऐसे मामले हो सकते हैं जहां ठेकेदार उचित खाता या खातों को बनाए नहीं रखा है उसके द्वारा बनाए रखा जाना विश्वास के योग्य नहीं पाया जाता है आकलन प्राधिकारी द्वारा. उस घटना में, एक सवाल होगा पूर्वोक्त प्रमुखों की ओर कटौती कैसे होती है बनाया जा सकता है. राज्यों की ओर से यह आग्रह किया गया है कि यह राज्य के लिए एक सूत्र निर्धारित करने की अनुमति होगी के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर श्रम और सेवाओं

और के प्रति खर्च के रूप में अनुबंध कार्य अनुबंध के मूल्य से कटौती की जा सकती है और कहा कि उक्त सूत्र को सभी कार्यों के लिए समान नहीं होना चाहिए अनुबंध और कार्यों की प्रकृति पर निर्भर हो सकता है अनुबंध. हम इस सबमिशन में योग्यता पाते हैं. ऐसे मामलों में जहां ठेकेदार उचित खातों या नहीं रखता है उसके द्वारा बनाए गए खाते योग्य नहीं पाए जाते हैं यह हमारे विचार में, राज्य के लिए स्वीकार्य होगा निर्धारण के लिए एक सूत्र निर्धारित करने के लिए कानून किसी विशेष को ठीक करके श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क कार्य अनुबंध के मूल्य का प्रतिशत और अनुमति देना मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से कार्य अनुबंध के मूल्य से निर्धारित राशि की कटौती कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल. हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कटौती योग्य राशि उस सूत्र के तहत जो कटौती के लिए निर्धारित है श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क अलग-अलग नहीं हैं श्रम और सेवाओं के लिए खर्च से जो होगा उस के संबंध में सामान्य परिस्थितियों में किया गया विशेष प्रकार के कार्य अनुबंध. के लिए खर्च के बाद से श्रम और सेवाएं प्रकृति की प्रकृति पर निर्भर करेंगी

<sup>9</sup>(1993) 1 एससीसी 364

अनुबंध काम करता है और सभी प्रकार के लिए समान नहीं होगा काम करता है अनुबंध, यह अनुमेय होगा, वास्तव में आवश्यक है, अलग-अलग निर्धारित करने के लिए, लागत के कारण कटौती के लिए तराजू विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुबंधों के लिए श्रम और सेवाएं.

50. एक सवाल उठाया गया है कि क्या यह स्वीकार्य है राज्य विधानमंडल गिरती बिक्री पर कर लगाने के लिए के निष्पादन में शामिल सभी सामानों के लिए कर की एक समान दर निर्धारित करके अनुच्छेद 366 (29-ए) (बी) के दायरे में एक काम अनुबंध भले ही कर की विभिन्न दरें हैं ऐसे सामानों की बिक्री के लिए निर्धारित है. के लिए सीखा वकील ठेकेदारों ने आग्रह किया है कि यह स्वीकार्य नहीं होगा की बिक्री के संबंध में कर की दो अलग-अलग दरों को लागू करने के लिए एक ही लेख, एक दर जब लेख अलग से बेचा जाता है और कनेक्शन में बिक्री को समझने पर एक अलग दर एक कार्य अनुबंध के निष्पादन के साथ. की ओर से राज्यों ने यह प्रस्तुत किया है कि यह स्वीकार्य है शामिल सभी वस्तुओं पर कर की एक विशेष दर लगाने के लिए राज्य एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में जो अलग हो सकता है बेचा जाने पर उन वस्तुओं पर लागू कर की दरों से अलग से. कराधान के क्षेत्र में इस न्यायालय के निर्णय विधायिका को एक अत्यंत व्यापक अभ्यास करने की अनुमति दी है कर उद्देश्यों के लिए वस्तुओं को वर्गीकृत करने में विवेक, जब तक यह स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण भेदभाव के खिलाफ है विशेष व्यक्ति या वर्ग. ईस्ट इंडिया टोबाको कंपनी v देखें. आंध्र प्रदेश राज्य, 1983 (1) एससीआर 404, पी पर. 411, पी.एम. अश्वथनारयन शेट्टी और ऑर्स। वी. कर्नाका राज्य और ऑर्स।, 1988 सप। (3) एससीआर 155 पी पर. 188; होटल फेडरेशन & और भारत के रेस्तरां एसोसिएशन वी. भारत संघ, : [१ ९ 1989] १ 178 आईटीआर ९ 97 (एससी); और केरल होटल और रेस्तरां एसोसिएशन और ओआरएस। वी. केरल और ओरस राज्य: [1990] 1 एससीआर 516. विभिन्न दरों पर बिक्री कर का कार्यान्वयन वार्षिक कारोबार के मूल्य के आधार पर इसमें बरकरार रखा गया था एस. कोडर बनाम केरल राज्य: [१ ९ :५] १ एससीआर १२१. इसी तरह, गंगा चीनी में चीनी मिलों और खंदरी इकाइयों के लिए अलग-अलग दरों पर खरीद कर लगाने को बरकरार रखा गया कं. लिमिटेड वी. यू.पी. और ओआरएस।: [1980] 1SCR 769. में हमारी राय, इसलिए, यह राज्य के लिए स्वीकार्य होगा एक समान दर पर एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सभी सामानों पर कर लगाने के लिए विधान जो व्यक्तिगत वस्तुओं पर लागू दरों से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि सामान जो कार्यों के निष्पादन में शामिल हैं

269LLR. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

कार्यों में शामिल होने पर अनुबंध को वर्गीकृत किया जा सकता है कर लगाने के उद्देश्य से एक अलग श्रेणी में

और ऐसे सामानों की बिक्री के लिए एक समान दर निर्धारित की जा सकती है.

51. पूर्वोक्त चर्चा निम्नलिखित की ओर ले जाती है निष्कर्ष: -

1. बिक्री पर कर लगाने की अपनी विधायी शक्ति के प्रयोग में या राज्य सूची के प्रवेश 54 के तहत माल की खरीद पढ़ें अनुच्छेद 366 (29-ए) (बी) के साथ, राज्य विधानमंडल, जबकि माल के हस्तांतरण पर कर लगाना (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) के निष्पादन में शामिल हो इस तरह के एक पर कर लगाने के लिए एक कार्य अनुबंध सक्षम नहीं है स्थानांतरण (डीमंड बिक्री) जो पाठ्यक्रम में बिक्री का गठन करता है अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य या राज्य के बाहर बिक्री या आयात या निर्यात के दौरान बिक्री.
2. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 और धारा 14 और 15 के प्रावधान लागू हैं के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण अनुच्छेद 366 (29-ए) (बी) द्वारा कवर अनुबंध काम करता है.
3. बिक्री कर में अभिव्यक्ति 'बिक्री' को परिभाषित करते हुए कानून यह राज्य विधानमंडल के लिए साइट्स को ठीक करने के लिए खुला है एक समझा बिक्री के परिणामस्वरूप एक हस्तांतरण के भीतर गिर रहा है अनुच्छेद 366 (29-ए) (बी) के दायरे में लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है के रूप में कर शक्ति के दायरे में लाने के लिए एक बिक्री अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य का कोर्स, या बाहर की बिक्री आयात और निर्यात के दौरान राज्य या बिक्री.
4. माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर (चाहे के रूप में माल या किसी अन्य रूप में) एक के निष्पादन में शामिल अनुच्छेद 366 (29-) के दायरे में आने वाले अनुबंध पर काम करता है ए) (बी) के निष्पादन में शामिल माल पर लगाया जा सकता है अनुबंध और माल का मूल्य जो काम करता है कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल होगा कर लगाने का उपाय.
5. माल के मूल्य का निर्धारण करने के लिए जो हैं के लिए एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल है अनुच्छेद 366 में उल्लिखित कर लगाने का उद्देश्य (29- ए) (बी), कार्यों का मूल्य लेने की अनुमति है आधार और माल के मूल्य के रूप में अनुबंध कार्य अनुबंध के निष्पादन पर आ सकता है

प्रदान करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए खर्चों में कटौती कार्यों के मूल्य से श्रम और अन्य सेवाएं अनुबंध.

6. श्रम और सेवाओं के लिए शुल्क जो आवश्यक हैं कार्य अनुबंध के मूल्य से कटौती की जाएगी कार्यों के निष्पादन के लिए कवर (i) श्रम शुल्क, (ii) श्रम और सेवाओं के लिए एक उप-ठेकेदार को भुगतान की गई राशि; (iii) कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले भाड़े या अन्यथा मशीनरी और उपकरणों पर प्राप्त करने के लिए शुल्क; (iv) शुल्क योजना, डिजाइन और वास्तुकार की फीस के लिए; और (v) की लागतकार्यों के अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली उपभोग्य वस्तुएं; (vi) ठेकेदार की स्थापना की लागत इस हद तक है श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए भरोसेमंद, (vii) अन्य समान श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए खर्च करने योग्य; तथा (viii) ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ इस हद तक है श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए भरोसेमंद.
7. उन मामलों से निपटने के लिए जहां ठेकेदार नहीं करता है उचित खातों या द्वारा उत्पादित खाता पुस्तकों को बनाए रखें उसे मूल्यांकन के योग्य नहीं पाया जाता है विधायिका के अधिकार के लिए एक सूत्र लिख सकते हैं के आधार पर श्रम और सेवाओं की लागत में कटौती कार्य अनुबंध के मूल्य का प्रतिशत लेकिन जबकि ऐसा करने से यह सुनिश्चित करना होगा कि कटौती योग्य राशि इस तरह के फार्मूले के तहत सराहनीय रूप से भिन्न नहीं है श्रम और सेवाओं के लिए खर्च जो इसमें खर्च किया जाएगा उस विशेष प्रकार के संबंध में सामान्य परिस्थितियां काम करता है अनुबंध. यह विधायिका के लिए स्वीकार्य होगा की लागत के कारण कटौती के लिए अलग-अलग तराजू निर्धारित करें विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुबंध के लिए श्रम और सेवाएं.

8. कर की दर तय करते समय इसे ठीक करने की अनुमति है में शामिल विभिन्न सामानों के लिए कर की एक समान दर एक कार्य अनुबंध का निष्पादन जो दर अलग हो सकती है बिक्री या खरीद के संबंध में तय किए गए

(28) एक अन्य अवसर पर, जहाँ डेवलपर्स थे के भुगतान पर संभावित खरीदारों के लिए निर्माण करने का उपक्रम इस तरह के निर्माण / विकास के लिए समझौते में निर्धारित विभिन्न किस्तों में कीमत, वैट के तहत कर की समस्या थी में एपेक्स कोर्ट के दो न्यायाधीश बेंच द्वारा विचार किया गया

27 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

विकास निगम बनाम कर्नाटक राज्य<sup>10</sup> जिसमें यह था के तहत आयोजित: -

काम करता है अनुबंध एक खरीदार के साथ दर्ज एक विशिष्ट समझौते को देखने की जरूरत है। प्रासंगिक धारा हैं धारा (क्यू), (आर)की भर्तियों और धारा 1, 5 (सी) और 7, जो निम्नानुसार पढ़ते हैं:

इमारत;

(ii) पूर्वोक्त बहु-मंजिला इमारत में इकाइयों की बिक्री अलग-अलग व्यक्तियों के लिए जिनके पक्ष में अंततः एक डीड है सीधे होल्डर्स द्वारा प्राप्त किया जाएगा विक्रेताओं से, में एक अविभाजित आंशिक ब्याज की कहा भूमि (यानी 5910.17 वर्ग मीटर का क्षेत्र) में वर्णित है पहली अनुसूची यहाँ लिखी गई है) और इकाइयों के ऐसे मालिक स्वामित्व के आधार पर, संबंधित इकाइयों पर स्वामित्व होगा शर्त है कि एक समझौते के बीच में प्रवेश किया जाएगा एक ओर धारक और दूसरी ओर व्यक्ति (ऐसी बहुमंजिला इमारत में एक इकाई के स्वामित्व के आधार पर अधिग्रहण करने के इच्छुक) और यह एक आवश्यक होगा, अभिन्न और बुनियादी अवधारणा, शब्द और स्थिति प्रस्तावित लेनदेन (जो एक पैकेज के माध्यम से होगा अलग या अलग होने में सक्षम नहीं है या पर संबंधित प्रभाव के बिना एक को समाप्त कर दिया अन्य) कि के. भूमि के रूप में रहजा विकास निगमधारक ऐसे व्यक्तियों को बेचने के लिए सहमत होगा जो पहले में वर्णित उक्त भूमि में एक अविभाजित आंशिक ब्याज है यहां अनुसूची इस शर्त पर लिखी गई है कि वे अर्थात् एम / एस क. विकास निगम पर डेवलपर्स के रूप में ऐसे व्यक्ति के डेवलपर्स की ओर से निर्माण होगा के लिए, एक इकाई के रूप में अंततः ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो एक इकाई या इकाइयाँ जो इतनी पारस्परिक रूप से चयनित और व्यवस्थित होंगी और के बीच. राहजा विकास निगम और संबंधित व्यक्ति;

आर) संभावित खरीदार प्राप्त करने में रुचि रखता है यूनिट / एस के संबंध में स्वामित्व अधिकार 1101 पर उक्त बहुमंजिला इमारत की ग्यारहवीं मंजिल राहेजा टावर्स 'और कार पार्किंग स्पेस / एस नं।

<sup>10</sup>(2005) 5 एससीसी 162

उक्त भवन का तहखाना / भूतल (इसके बाद) 'उक्त इकाई' के रूप में जाना जाता है)"

XXXX XX

1. पैकेज डील के रूप में :

1. क. रहजा विकास निगम, (होल्डर्स के रूप में) भावी क्रेता को एक अविभाजित बेचने के लिए सहमत उक्त भूमि में 0.42% हिस्सेदारी, अधिकार, शीर्षक और ब्याज पहली अनुसूची में वर्णित है (नहीं के साथ) किसी भी अलग उप का दावा करने के लिए संभावित खरीदार का अधिकारविभाजन और / या किसी भी हिस्से के अनन्य कब्जे का अधिकार उक्त भूमि) एकमुश्त सहमति और मात्रा निर्धारित करने के लिए

'3,25,000 / - (रुपये तीन लाख पच्चीस) पर विचार

हजार केवल) संभावित खरीदार द्वारा भुगतान किया जाना है क्लॉज 2 में उस समय और तरीके से होल्डर्स यहाँ;

2. क. रहजा विकास निगम, (डेवलपर्स के रूप में) 'रहेजा टावर्स' नामक उक्त इमारत के निर्माण के लिए सहमत',

इसमें विशिष्टताओं और सुविधाओं का होना तय है दूसरी अनुसूची यहाँ लिखी गई है और डेवलपर्स के रूप में भावी खरीदार, डेवलपर्स के लिए निर्माण करेंगे और यूनिट / एस के रूप में संभावित खरीदार से संबंधित है, उक्त परिसर (विवरण जहां तीसरी अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं यहां लिखा गया है) एकमुश्त सहमति और मात्रा निर्धारित करने के लिए

'5,07,000 / - (रुपये पांच लाख सात) पर विचार

हजार केवल) संभावित खरीदार द्वारा भुगतान किया जाना है उस समय और अंदर निर्धारित तरीके से डेवलपर्स धारा 3 इसके बाद. उक्त परिसर में सुविधाएं होंगी यहां लिखी गई चौथी अनुसूची में सेट किया गया है.

XX XX XX

5. रेखांकित नियम और प्रावधान व्यक्त किए गए हैं द्वारा देखी जाने वाली, प्रदर्शन की जाने वाली और पूरी की जाने वाली शर्तें संभावित खरीदार, जिसके आधार पर यह समझौता धारक / विकासकर्ताओं और नियत द्वारा दर्ज किया गया है और उचित पूर्ति जिसके लिए शर्तें हैं किसी भी शीर्षक से पहले बनाया जा रहा है और / या सक्षम है में संभावित खरीदार द्वारा प्रलेखित किया जा रहा है

2731.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

पहले में वर्णित भूमि में पूर्वोक्त आंशिक ब्याज यहां लिखित और / या उक्त परिसर में अनुसूची:

1. XX XX XX
2. XX XX XX
3. परियोजना का समग्र नियंत्रण और प्रबंधन और उक्त भवन का विकास और पूर्णता होगा डेवलपर्स के साथ रहें और इसके अलावा डेवलपर्स हैं और उक्त भूमि और भवन के कब्जे में रहना जारी रहेगा और एक ग्रहणाधिकार का हकदार होगा और वह संभावित क्रेता दावा करने का हकदार नहीं होगा या के किसी भी हिस्से पर होल्डर्स के कब्जे से मांग कहा भूमि या डेवलपर्स से दावा या मांग करने के लिए जब तक और जब तक उक्त परिसर का कब्जा नहीं हो जाता संभावित खरीदार ने होल्डर्स के माध्यम से पूर्ण भुगतान किया है के तहत धारकों के लिए देय पूर्ण विचार धन ऊपर दिए गए धारा 2 और ऊपर दिए गए धारा 3 के तहत डेवलपर्स को देय पूर्ण विचार धन.

XXXX XX

7. यदि प्रॉस्पेक्टिव क्रेता भुगतान में डिफॉल्ट रूप से काम करता है विचार की किसी भी किस्त को उनके ऊपर छोड़ दिया गया संबंधित नियत तारीखें (अनुबंध का सार होने का समय) और / या किसी भी शब्द का अवलोकन और प्रदर्शन करने में और इस समझौते की शर्तें, धारक / विकासकर्ता करेंगे 15 दिनों के नोटिस देने के बाद, ब्रीच को निर्दिष्ट करने के बाद और यदि उसी के भीतर सुधार नहीं किया गया है, तो स्वतंत्रता पर रहें समय, इस समझौते को समाप्त करने के लिए, किस घटना में, एक राशि 10% राशियों के बराबर जो तब तक हो सकती है धारकों को संभावित खरीदार द्वारा भुगतान किया गया है और डेवलपर्स क्रमशः जब्त किए जाएंगे. द हालांकि, धारकों और डेवलपर्स ऐसे पर होंगे समाप्ति, संभावित खरीदार को शेष राशि वापस करना भाग भुगतान की किस्तों की मात्रा, यदि कोई हो, जो तब तक संभावित खरीदार द्वारा भुगतान किया जा सकता है धारकों और डेवलपर्स क्रमशः लेकिन बिना किसी के ब्याज के माध्यम से या अन्यथा आगे की राशि. पर धारक / विकासकर्ता इस धारा के तहत इस

समझौते को समाप्त कर रहे हैं, वे उक्त इकाई / एस को निपटाने के लिए स्वतंत्र होंगे और किसी अन्य के लिए भूमि में उक्त आंशिक ब्याज व्यक्ति के रूप में वे फिट हैं, ऐसी कीमत पर जैसा कि वे निर्धारित कर सकते हैं

*CUD डेवलपर लिमिटेड, KARNAL v. हरियाणा और 274 अन्य लोगों की स्थिति (अजय कुमार मित्तल, जे।)*

और संभावित खरीदार का हकदार नहीं होगा ऐसी बिक्री, निपटान या किसी भी राशि का दावा करने के लिए सवाल उन्हें."

20. इस प्रकार अपीलकर्ता निर्माण करने का उपक्रम कर रहे हैं भावी खरीदार के लिए डेवलपर्स. ऐसा निर्माण / विकास में एक कीमत के भुगतान पर होना है समझौते में निर्धारित विभिन्न किस्तें. जैसा कि अपीलकर्ता वे मालिक नहीं हैं जिन पर वे "ग्रहणाधिकार"का दावा करते हैं संपत्ति. बेशक, धारा 7 के तहत उनके पास अधिकार है समझौते को समाप्त करना और यदि इकाई को बंद करना है तो ए ब्रीच क्रेता द्वारा किया जाता है. हालाँकि, केवल इस तरह के एक धारा होने का मतलब यह नहीं है कि समझौता शब्द के अर्थ के भीतर एक कार्य अनुबंध होना बंद हो जाता है उक्त अधिनियम में। इसका मतलब यह है कि अगर वहाँ एक है समाप्ति और उस विशेष इकाई को फिर से बेचा नहीं जाता है लेकिन बनाए रखा जाता है अपीलकर्ताओं द्वारा, उस पर कोई कार्य अनुबंध नहीं होगा हद. लेकिन जब तक कोई समाप्ति नहीं होती है निर्माण क्रेता की ओर से और उसके लिए है. इसलिए, यह शब्द के अर्थ के भीतर एक कार्य अनुबंध बना हुआ है उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि फ्लैट या यूनिट पहले से ही होने के बाद समझौता किया जाता है निर्माण किया, तो कोई काम अनुबंध नहीं होगा. लेकिन ऐसा है जब तक निर्माण से पहले समझौता किया जाता है ई /एफआरपी

(२९) में निर्णय की शुद्धता क. राहजा विकास निगम का मामला (सुपर) बाद के अवसर पर संदेह किया गया था लार्सन का मामला (सुप्रा) और यह एपेक्स कोर्ट द्वारा महसूस किया गया था कि निर्णय को एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी. तीन सुप्रीम कोर्ट की जज बेंच लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का मामला (सुप्रा) में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को बनाए रखना क. राहजा विकास निगम का मामला (सुप्रा), के रूप में कानूनी स्थिति संक्षेप: -

एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में बेचा गया है, तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए: (एक) एक काम होना चाहिए अनुबंध, (दो)माल में शामिल होना चाहिए था एक कार्य अनुबंध का निष्पादन और (तीन) उन सामानों में संपत्ति को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जाना चाहिए माल या किसी अन्य रूप में.

(ii) एक इमारत में अनुच्छेद ३६६ (२९-ए) (बी) के प्रयोजनों के लिए निर्माण करने के लिए अनुबंध या कोई अनुबंध, यदि डेवलपर

*275 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)*

मूल्यवान विचार प्राप्त करने के लिए प्राप्त या हकदार है, उपरोक्त तीन चीजें पूरी तरह से पूरी होती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि भवन के निर्माण के लिए एक अनुबंध के प्रदर्शन में, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ईंटों आदि जैसे सामान (चैटटेल) हैं संरचना में शामिल होने का इरादा है और भले ही उन्होंने माल के रूप में अपनी पहचान खो दी लेकिन यह कारक नहीं है उन्हें माल होने से रोकें.

3. जहां एक अनुबंध में दोनों कार्य अनुबंध शामिल होते हैं और अचल संपत्ति का हस्तांतरण, इस तरह के अनुबंध अनुबंध के रूप में अपने चरित्र से इनकार नहीं करते हैं. शब्द 'Z' अपने भीतर ले जाता है कार्य अनुबंध की सभी शैली को मोड़ो और एक तक सीमित नहीं है अकेले श्रम और सेवाओं के लिए प्रदान करने के लिए अनुबंध की कल्पना. अनुच्छेद 366 (29)(11) में कुछ भी नहीं
4. बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कार्य अनुबंध की प्रजातियां हैं.

5. एक अनुबंध में काम का अनुबंध और दोनों शामिल हो सकते हैं श्रम और बिक्री के लिए एक अनुबंध. ऐसे समग्र अनुबंध में, माल की बिक्री के लिए अनुबंध के बीच अंतर और काम (या सेवा) के लिए अनुबंध लगभग कम हो गया है.
6. प्रमुख प्रकृति परीक्षण का कोई अनुप्रयोग नहीं है और पारंपरिक निर्णय जो कि पदार्थ का आयोजन करते हैं अनुबंध को देखा जाना चाहिए जहां उनका महत्व खो गया है लेन-देन अनुच्छेद में चिंतनित प्रकृति के होते हैं 366 (29-ए). भले ही अनुबंध का प्रमुख उद्देश्य हो माल में संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए नहीं और बल्कि यह है सेवा का प्रतिपादन या अंतिम लेनदेन अचल संपत्ति का हस्तांतरण है, फिर यह राज्यों को लेवी के लिए भी खुला है इस तरह के अनुबंध में प्रयुक्त सामग्री पर बिक्री कर यदि ऐसा है अनुबंध अन्यथा कार्य अनुबंध के तत्व हैं. द प्रवर्तनीयता परीक्षण भी निर्धारक नहीं है.
7. अनुच्छेद 366 के धारा 29-ए (बी) के तहत माल में संपत्ति का हस्तांतरण व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल की बिक्री माना जाता है व्यक्ति द्वारा उन सामानों का स्थानांतरण और खरीद जिसे इस तरह का ट्रांसफर किया जाता है.
8. यहां तक कि एक एकल और अविभाज्य कार्यों के अनुबंध में, द्वारा अनुच्छेद 366 (29-) द्वारा पेश कानूनी कथा का गुण ए) (बी), माल की एक डीमंड बिक्री है जो इसमें शामिल हैं

कार्य अनुबंध का निष्पादन. इस तरह की एक बिक्री है में शामिल माल की बिक्री की सभी घटनाएं एक कार्य अनुबंध का निष्पादन जहां अनुबंध विभाज्य है माल की बिक्री के लिए एक में और दूसरा आपूर्ति के लिए श्रम और सेवाएं. दूसरे शब्दों में, एकल और अविभाज्य अनुबंध, अब चालीस-छठे संशोधन द्वारा किया गया है दो अलग-अलग अनुबंध वाले सममूल्य पर लाया गया है समझौतों और राज्यों पर अब बिक्री कर लगाने की शक्ति है कार्य अनुबंध के निष्पादन में सामग्री का मूल्य.

(ix) सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 54 जब के साथ पढ़ा जाता है अनुच्छेद 366 की परिभाषा धारा 29-ए में कर शामिल है माल के रूप में या माल में संपत्ति का हस्तांतरण कार्यों के निष्पादन में शामिल माल के अलावा अन्य रूप अनुबंध.

(x) अनुच्छेद 366 (29-ए) (बी) लेनदेन लाने के लिए कार्य करता है आवश्यक सामग्री अधिनियम, 1930 बिक्री या खरीद के दायरे में अनुपस्थित हैं बिक्री कर लगाने के उद्देश्य. दूसरे शब्दों में, का स्थानांतरण एक कार्य अनुबंध में चल संपत्ति को बिक्री माना जाता है भले ही यह अर्थ के भीतर बिक्री न हो माल अधिनियम की बिक्री.

(xi) एक कार्य अनुबंध में माल तत्व की बिक्री पर कर लगाना अनुच्छेद 366 (29-ए) (बी) के तहत प्रविष्टि 54 सूची II के साथ पढ़ा जाता है माल प्रदान करने के बाद भी अनुमेय कर माल के मूल्य के लिए निर्देशित किया जाता है और कर के लिए शुद्ध नहीं होता है अचल संपत्ति का हस्तांतरण. माल का मूल्य जो कर के लेवी के लिए उपाय का गठन कर सकता है के निगमन के समय माल का मूल्य होना काम में माल भले ही संपत्ति के बीच से गुजरता है डेवलपर और फ्लैट क्रेता को शामिल करने के बाद

(30) सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य सिद्धांतों में, कानूनी सिद्धांतों को क्रिस्टलीकृत किया शब्दों ने कहा था कि प्रमोटर / बिल्डर के बीच समझौता/डेवलपर और फ्लैट क्रेता एक फ्लैट का निर्माण करने के लिए और उसके बाद बेचते हैं भूमि के कुछ हिस्से के साथ फ्लैट, निर्माण की गतिविधि को शामिल करता है कार्य करने या निष्पादित करने के लिए बाध्य. निर्माण की गतिविधि कार्य अनुबंध की सभी विशेषताएं, तत्व और विशेषताएं हैं

277I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

हालांकि अनिवार्य रूप से यह फ्लैट की बिक्री का लेनदेन हो सकता है. इसे लगाने के लिए अलग तरह से, जब तक निर्माण के लिए और की ओर से है

(31) इसके अलावा, निरंतरता के लिए आवश्यक शर्तें पूरी की जानी चाहिए माल पर कर का लगान एक के निष्पादन में बेचा गया है



1. एक कार्य अनुबंध होना चाहिए,
2. माल के निष्पादन में शामिल होना चाहिए था एक काम अनुबंध, और
3. उन सामानों की संपत्ति को एक तिहाई में स्थानांतरित किया जाना चाहिए पार्टी या तो सामान के रूप में या किसी अन्य रूप में.

(32) ये शर्तें किसी भवन अनुबंध या किसी में पूरी होती हैं निर्माण करने का अनुबंध. एक फ्लैट बनाने के लिए एक अनुबंध में, जरूरी है इसमें शामिल वस्तुओं की बिक्री का एक तत्व होगा और इसलिए, निर्माण अनुबंध कार्य अनुबंध की प्रजातियां हैं. अभी भी आगे, ए अनुबंध जिसमें एक कार्य अनुबंध और एक हस्तांतरण दोनों शामिल हैं अचल संपत्ति, इस तरह के अनुबंध के अपने चरित्र से इनकार नहीं किया जाता है एक काम अनुबंध किया जा रहा है. के संविधान का अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) भारत ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां माल नहीं हो सकता है माल के रूप में स्थानांतरित किया गया है, लेकिन कुछ अन्य में स्थानांतरित किया जा सकता है वह रूप जो अचल संपत्ति के रूप में भी हो सकता है. इसमें कोई शर्क नहीं, कर लगाने के लिए राज्य विधायिका में कोई विधायी क्षमता नहीं है की सूची II के प्रवेश 54 के तहत अचल संपत्ति का हस्तांतरण सातवीं अनुसूची. हालांकि, राज्यों को बिक्री कर लगाने का अधिकार है फ्लैट की बिक्री के एक समझौते में माल की बिक्री पर जो भी एक है माल की एक बिक्री का घटक.

(33) एक बार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर हैं एक समझौते में प्रवेश करते समय कार्य अनुबंध के तहत कवर किया गया उनके और फ्लैट क्रेता के बीच एक फ्लैट और अंततः निर्माण करने के लिए जमीन के अंश के साथ फ्लैट बेचते हैं, हम व्यापक की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं के हस्तांतरण से संबंधित कर योग्य कारोबार का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत ऐसे कार्यों के अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामान. जहां डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर / ठेकेदार या उप-ठेकेदार रखता है खाते की उचित पुस्तकें, यह शामिल माल का मूल्य होगा खाते की पुस्तकों के अनुसार कार्य अनुबंध में दूसरी ओर, जहां डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर / ठेकेदार / उप-ठेकेदार नहीं करता है उचित खाते बनाए रखें या उसके द्वारा बनाए गए खाते नहीं हैं विश्वसनीयता के योग्य पाया गया, यह राज्य के लिए स्वीकार्य होगा के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए एक सूत्र निर्धारित करने के लिए विधानमंडल

का एक विशेष प्रतिशत तय करके भूमि का श्रम, सेवा और लागत अनुबंध काम करता है और इस प्रकार निर्धारित राशि की कटौती की अनुमति देता है के मूल्य का आकलन करने के लिए कार्य अनुबंध के मूल्य से कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामान. कर योग्य घटना निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण है एक कार्य अनुबंध और ऐसे सामानों में संपत्ति का उक्त हस्तांतरण होता है जगह जब माल कार्यों में शामिल किया जाता है. का मूल्य माल जो कर के लेवी के लिए उपायों का गठन कर सकता है, माल के निगमन के समय माल का मूल्य होना चाहिए काम करता है. डेवलपर द्वारा किए गए निर्माण की गतिविधि आदि. वह केवल एक अनुबंध में प्रवेश करने वाले चरण से अनुबंध का काम करेगा फ्लैट क्रेता के साथ. हालांकि, कटौती के तहत अनुमेय विभिन्न प्रमुख प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्भर करेंगे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री. यह स्पष्ट किया जाता है कि समझौता कहां है फ्लैट या यूनिट के पूरा होने के बाद प्रवेश किया गया, कार्य अनुबंध का कोई तत्व नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में, जहां समझौता है निर्माण पूरा होने से पहले प्रवेश किया, यह एक काम होगा अनुबंध. यदि निर्माण के समय और निर्माण होने तक पूरा, भवन के निर्माण के लिए कोई अनुबंध नहीं था फ्लैट खरीदार, निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामान को नहीं समझा जा सकता है बिल्डर द्वारा बेचा गया है उस समय से कोई खरीदार नहीं है यहां तक कि अगर निर्माण के बाद बेचा जाने का इरादा है, तो कोई परिणाम नहीं होगा. के बाद हस्तांतरित माल के लिए किए गए मूल्य जोड़ फ्लैट क्रेता के साथ समझौता किया जाता है जिसे केवल बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा कर के लिए प्रभार्य. अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) के तहत एक कार्य अनुबंध में माल तत्व की बिक्री पर कर लगाना भारत के संविधान की अनुसूची VII की 54 सूची II अनुमेय है प्रदान किए गए माल को शामिल करने के बाद भी मूल्य को निर्देशित किया जाता है निगमन के समय माल की और कर लगाने के लिए नहीं है अचल संपत्ति का हस्तांतरण. से कोई कर नहीं लिया जा सकता है के मूल्य के संबंध में डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर या ठेकेदार के साथ समझौते के बाद काम के अनुबंध में शामिल माल फ्लैट क्रेता जिस पर उप-ठेकेदार ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है.

(३४) अगला, यह याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील द्वारा दावा किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य ने *UPVAT* नियमों के नियम 9 को तैयार किया है, दिल्ली वैट नियम, 2005 के नियम 3 के तहत 2005 और दिल्ली राज्य के लेनदेन पर वैट लगाने के लिए विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए डेवलपर्स आदि जबकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. द डेवलपर जो निर्माण गतिविधियों को स्वयं नहीं करता है लेकिन उस काम के लिए उप ठेकेदार बनाता है, किसी भी कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अधिनियम के तहत। यह अकेले उप-ठेकेदार का दायित्व होगा

279 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

उसके द्वारा किए गए कार्यों के अनुबंध का खाता. आगे विस्तार करते हुए, यह आग्रह किया गया था कि एक डेवलपर के फ्लैट की बिक्री के लेन-देन के मामले में एक खरीदार, यदि कर वसूला जा सकता है, तो यह केवल मूल्य पर हो सकता है प्रवेश की तारीख के बाद और बाद में कार्यों में शामिल सामग्री अचल संपत्ति की बिक्री के लिए समझौते में और निर्देशित नहीं किया जा सकता है अचल संपत्ति के मूल्य पर. हालांकि, अधिनियम और नियम सम्मिलित नहीं हैं अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के कारण कोई कटौती:

1. अचल संपत्ति, और
2. अन्य सभी खर्चों का मूल्य जो कि भरोसेमंद नहीं हैं माल की आपूर्ति जैसे
  1. EDC
  2. आईडीसी
  3. भूमि उपयोग शुल्क में परिवर्तन
  4. नक्शे को मंजूरी देने के लिए शुल्क
  5. नक्शे के प्रसंस्करण के लिए शुल्क
  6. विपणन व्यय, आदि.
  7. वित्त शुल्क
  8. स्टॉप शुल्क
  9. कानूनी खर्च
  10. श्रम उपकर
  11. जांच शुल्क
  12. आग, जंगल जैसे विभिन्न अनुमोदन के लिए शुल्क, पर्यावरण, विमानन आदि.
  13. अन्य शुल्क / लागत / व्यय हस्तांतरण के लिए भरोसेमंद नहीं हैं माल में संपत्ति की.
  14. समान व्यय जिसमें कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है काम के अनुबंध के निष्पादन में माल की संपत्ति लेकिन के व्यवसाय पर ले जाने में आकस्मिक हैं डेवलपर आदि.

(३५) अभी भी आगे, जैसा कि सीखा वकील, स्पष्टीकरण (i) से आग्रह किया गया है अधिनियम की धारा 2 (1) (zg) केवल श्रम के संबंध में बहिष्करण प्रदान करती है और अन्य सेवा शुल्क. इसी तरह नियमों के नियम 25 (2) भी अकेले उस खाते पर कटौती के लिए प्रदान करता है. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक डेवलपर आदि के लिए इन प्रावधानों के आवेदन पर, का मूल्य

*CUD डेवलपर लिमिटेड, KARNAL v. हरियाणा और 280 अन्य लोगों की स्थिति (अजय कुमार मित्तल, जे।)*

अचल संपत्ति और अन्य खर्च आकस्मिक उपचार जो हैं फ्लैट की बिक्री के लेन-देन का अभिन्न अंग, बाहर नहीं किया जाएगा और जिसका शुद्ध प्रभाव उस पर कर लगाने के बजाय होगा हस्तांतरित सामग्रियों का मूल्य, प्रावधानों के मूल्य के कर लगाने की ओर जाता है अचल संपत्ति और खर्च सामग्री के मूल्य से संबंधित नहीं हैं. नियमों के नियम 25 (2) केवल घटना में कटौती विधि के लिए प्रदान करते हैं श्रम और सेवाओं का लेकिन अचल के मूल्य को कम नहीं करता है संपत्ति. दोनों प्रावधानों की वैधता को परीक्षण के लिए रखा गया था याचिकाकर्ताओं के लिए वकील सीखा.

36. निर्देशों की वैधता से संबंधित शिकायत भी उठाई गई थी दिनांक 7.5.2013, 4.6.2013 और 10.2.2014 (अनुलग्नक पी -2 कोली). निर्देश सं. 952 / ST-1 दिनांक 7.5.2013 (अनुलग्नक पी -2) द्वारा जारी किया गया प्रतिवादी नंबर 2 प्रदान करता है कि समझौतों / अनुबंधों द्वारा दर्ज किया गया पहले अपार्टमेंट / फ्लैट की बिक्री के लिए संभावित खरीदारों के साथ डेवलपर्स निर्माण का पूरा होना 'अनुबंध का काम करता है' और इस प्रकार ऐसे लेनदेन पर वेट लगाया गया था. उक्त परिपत्र का धारा 4 श्रम और अन्य की तरह कर और कटौती की माप से संबंधित है शुल्क. बनाने के संबंध में परिपत्र दिनांक 4.6.2013 जारी किया गया था बिल्डरों और डेवलपर्स पर आकलन. कानूनी स्थिति को देखते हुए इसके अलावा, जारी करने में कोई अवैधता नहीं है परिपत्र दिनांक 7.5.2013 और 4.6.2013. हालाँकि, परिपत्र जारी किया गया 10.2.2014 रचना कर योजना के तहत एकमुश्त कर से संबंधित है और धारा 9 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए इससे निपटा गया है नियमों का अधिनियम और नियम 49.
37. स्पष्टीकरण (i) की वैधता की धारा की जांच करना अधिनियम के 2 (1) (zg) और नियमों के नियम 25 (2), यह आवश्यक होगा ध्यान दें कि असंवैधानिकता की घोषणा से बचने के लिए, न्यायालयों ने व्याख्या के ऐसे सिद्धांतों को अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप कानून को बनाए रखा जाएगा. शीर्ष न्यायालय की संविधान बेंच माध्या और अन्य राज्य बनाम एम / एस छोटाभाई जेठभाई पटेल एंड कंपनी और एक अन्य<sup>11</sup> पैरा 10 के तहत आयोजित किया गया था:

"यह कानून है कि जहां दो निर्माण एक विधायी प्रावधान संभव है कि एक के अनुरूप हो माप की संवैधानिकता और अन्य उसी को खारिज करते हुए, न्यायालय पहले की ओर झुक जाएगा यदि यह लागू किए गए उद्देश्य और उद्देश्य के अनुकूल हो अधिनियम, वह शरारत जिसे उसने पता लगाने से रोकने की मांग की थी प्रासंगिक कारकों से इसका सही दायरा और अर्थ है."

" AIR 1972 SC 971

2811.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

(3) इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट की एक और संविधान बेंच में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य<sup>12</sup>, पैरा 38 में के रूप में देखा गया था:

"विधानमंडल और के लिए संवैधानिक सम्मान लोकतांत्रिक धारणा है कि लोगों के प्रतिनिधि समुदाय की बुद्धिमत्ता को व्यक्त करते हैं, जो अदालतों की व्याख्या में उन विधियों की व्याख्या करते हैं जो वैधता को संरक्षित और बनाए रखते हैं प्रावधान. यह कहना है, अदालतों को बुद्धिमान होना चाहिए कल्पना, खुद को मूल्यों के बारे में सूचित करें संविधान और, कार्यात्मक लचीलेपन के साथ, अन्वेषण करें उस निर्माण को अपनाने के अर्थ का अर्थ जो मानवीय रूप से प्रश्न में कानून का संवैधानिककरण करता है. सादा कहा, हमें Ss.30 में शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास करना चाहिए और जेल अधिनियम के 56 और जेल के पैराग्राफ मैनुअल इस तरह से है कि जबकि शब्द के हैं पुराना क्रम, भावना नए क्रम को विकीर्ण करती है. 2007 के 17 वेम्स के सिविल राइट पेटिशन नंबर 6573 में चमकदार दिशानिर्देश वी.संयुक्त राज्य अमेरिका (1909) 54 एल एड 793 पी .801 पर हमारे दर्शनीय स्थल हैं उच्च: "विधान, वैधानिक और संवैधानिक दोनों है अधिनियमित, यह बुराइयों के अनुभव से सच है, लेकिन - इसका इसलिए सामान्य भाषा जरूरी नहीं होनी चाहिए उस रूप तक सीमित है जो बुराई थी, इसलिए लिया गया. समय परिवर्तन का काम करता है, नई परिस्थितियों को अस्तित्व में लाता है और प्रयोजनों. इसलिए, एक सिद्धांत, महत्वपूर्ण होने के लिए, सक्षम होना चाहिए शरारत की तुलना में व्यापक अनुप्रयोग जिसने इसे जन्म दिया. यह गठन का अजीब सच है. वो नहीं हैं अल्पकालिक अधिनियम, गुजरते अवसरों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया. वे मुख्य न्यायाधीश मार्शल के शब्दों का उपयोग करने के लिए हैं, "मानव के रूप में लगभग अमरता के लिए डिज़ाइन किया गया संस्थान इसे अपना सकते हैं "" भविष्य उनकी देखभाल है और अच्छी और बुरी प्रवृत्ति की घटनाओं के लिए प्रावधान जिनमें से नहीं

भविष्यवाणी की जा सकती है. एक संविधान के आवेदन में, इसलिए, हमारा चिंतन केवल वही नहीं हो सकता है जो हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है. किसी अन्य नियम के तहत ए संविधान वास्तव में आवेदन के रूप में आसान होगा होगा. किसी भी अन्य नियम के तहत एक संविधान वास्तव में होगा आवेदन के रूप में आसान हो सकता है क्योंकि यह प्रभावकारिता में कमी होगी और शक्ति. इसके सामान्य सिद्धांतों का बहुत कम मूल्य होगा, और मिसाल से नपुंसक और बेजान में परिवर्तित हो

<sup>12</sup> AIR 1978 SC 1675

सूत्रों. शब्दों में घोषित अधिकार वास्तविकता में खो सकते हैं. और इसे मान्यता दी गई है. अर्थ और संविधान की जीवन शक्ति संकीर्ण के खिलाफ विकसित हुई है और प्रतिबंधात्मक निर्माण."

39. व्याख्या के नियम की आवश्यकता है कि इस तरह के अर्थ चाहिए उस प्रावधान को सौंपा जाए जो अधिनियम का प्रावधान करेगा प्रभावी और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाना। यह किया जाना चाहिए जहां भी संभव हो, भाषा की कोई हिंसा किए बिना प्रावधान. न्याय करने के लिए एक कानून को इस तरह से पढ़ना पड़ता है पार्टियों को. इसके अलावा, एपेक्स कोर्ट में बी. आर. उद्यम बनाम यू.पी. राज्य<sup>13</sup>, कलकत्ता गुजराती शिक्षा सोसायटी बनाम कलकत्ता नगर निगम<sup>14</sup> तथा एम.नागरा बनाम भारत का संघ<sup>15</sup> है वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने के नियम की व्याख्या करने का मतलब है कि ए प्रावधान को बचाने के लिए वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर पढ़ा जाता है असंवैधानिक या अल्ट्रा वायर्स होने का उच्चारण किया जा रहा है. नीचे पढ़ने का नियम एक प्रावधान को सामंजस्यपूर्ण रूप से और सीधा करने के लिए है एक कानून को व्यावहारिक बनाने के लिए कूडिटी या इस्त्री करना कम हो जाता है.
40. अधिनियम की धारा 2 (1) (zg) के लिए स्पष्टीकरण (i) जो परिभाषित करता है के तहत परिभाषित सकल कारोबार से संबंधित सेवाएं रिम अनुबंध. यह एक चार्जिंग प्रावधान नहीं है जिसके लिए कोई दायित्व बनता है अधिनियम और प्रावधान इसके दायरे में कुछ नहीं करता है जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है. इस प्रकार, उक्त प्रावधान असंवैधानिकता के किसी भी उपाध्यक्ष या दोष से ग्रस्त नहीं है.
41. अब हम नियमों के नियम 25 का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं. कहा हुआ नियम श्रम, सेवाओं और अन्य के संबंध में बहिष्करण प्रदान करता है शुल्क और मूल्य के बहिष्करण के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है भूमि का. जहां भी डेवलपर / बिल्डर / प्रमोटर या उप ठेकेदार जो एक कार्य अनुबंध में निर्माण कार्य करता है, वह उचित रखता है खातों, यह के खाते पर वास्तविक मूल्य जोड़ के आधार पर होगा संपत्ति में उपयोग किए गए सामान. नियमों के नियम 25 (2) में श्रम, सेवाओं और अन्य जैसे शुल्कों में कटौती का प्रावधान है और जहां वे खातों की पुस्तकों से पता लगाने योग्य नहीं हैं एक डेवलपर आदि द्वारा बनाए रखा जाता है, प्रतिशत दरों में निर्धारित किया जाता है

<sup>13</sup> (1999) 9 एससीसी 700

<sup>14</sup> (2003) 10 एससीसी 533

<sup>15</sup> (2006) 8 एससीसी 212

283I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

उक्त नियम में दी गई तालिका. यह प्रदान करने के लिए आवश्यक है हस्तांतरित माल के लिए किए गए केवल मूल्य जोड़ पर कर लगाने के लिए तंत्रफ्लैट क्रेता के साथ समझौते के बाद. द 'डिडक्टिव मेथड' इसके अलावा किसी भी कटौती के लिए प्रदान नहीं करता है जो अचल संपत्ति के मूल्य से संबंधित है. विधायिका के मूल्य के बहिष्करण के

लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है काम के अनुबंध और इसकी विधि से अचल संपत्ति मूल्यांकन को नियम बनाने के अधिकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है लिखो.

(४२) राज्य ने २४.४.२०१४ को श्री बी.एल. गुप्ता, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा, जिसमें पैरा ३ से ८ इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

3

तृतीय

यह पुष्टि की जाती है कि डेवलपर्स / काम के ठेकेदार, सामान्य वैट डीलरों के रूप में मूल्यांकन किया जा रहा है, सभी के हकदार हैं कानून / नियमों के अनुसार स्वीकार्य कटौती.

4. हरियाणा वैट में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम, 2003 और उसके नियमों को लागू किया गया, कर होना है में शामिल माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया गया कार्य अनुबंध का निष्पादन. यह स्पष्ट किया जाता है कि परिभाषा 'माल' शब्द, जैसा कि धारा 2 (1) (आर) में उपलब्ध है हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, शामिल नहीं है अचल संपत्ति, अर्थात् भूमि.
5. वह अधिनियम *ibid*, जो 54, सूची II में प्रवेश करने के लिए भरोसेमंद है भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची प्रदान करती है माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए अखबार.
6. ऊपर के संबंध में, न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही क्या इसके निष्पादन में शामिल भूमि की कीमत पर लगाया जा सकता है काम करता है अनुबंध.
7. उत्तरदाताओं, कानून का पालन करने वाले अधिकारी होने के नाते, उपरोक्त संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते.

गैर-वैट डीलर (वॉर्क कंस्ट्रक्टर):

4. हालांकि, लेवी विज्ञ के संबंध में कुछ अंतर है-ए-विज्ञ नॉन-वैट डीलर यानी ठेकेदार के तहत काम करता है की धारा 9 के तहत प्रदान की गई रचना / एकमुश्त योजना नियमों के अधिनियम और नियम 49 को बनाया गया. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे काम करने वाले ठेकेदार, जो इसका विकल्प चुनते हैं पूर्वोक्त योजना का लाभ, एकमुश्त भुगतान करना आवश्यक है

*CUD डेवलपर लिमिटेड, KARNAL v. हरियाणा और 284 अन्य लोगों की स्थिति (अजय कुमार मित्तल, जे।)*

कुल मूल्यवान विचार पर कर के बदले में राशि कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए प्राप्य. अन्य में शब्द, कोई कटौती नहीं (भूमि के मूल्य सहित), है योजना के रूप में कुल मूल्य विचार से स्वीकार्य है प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने का इरादा है और गंध और विभाग दोनों के लिए सादगी. में एकमुश्त योजना, एक आसानी से देखने योग्य यार्ड स्टिक, जैसे कि इस मामले में कुल मूल्यवान विचार, गणना करने के लिए लिया जाता है कर की मात्रा का भुगतान किया जाना है. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून किसी भी कार्य ठेकेदार को व्यायाम करने के लिए बाध्य या बाध्य नहीं करता है उसकी मर्जी के खिलाफ यह विकल्प. वह अपने व्यायाम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है विकल्प. यदि पूर्वोक्त योजना उसके अनुरूप नहीं है, तो वह कर सकता है बहुत अच्छी तरह से उसी से बचना. प्रावधानों, के लिए भेजा ऊपर, सख्त व्याख्या सिद्धांत के आवेदन पर राजकोषीय कानून, संदेह का कोई तरीका नहीं छोड़ता है कि ऐसा है ठेकेदार हकदार नहीं है

43. किसी विशिष्ट की अनुपस्थिति में हलफनामे में दावा कानून या नियम में प्रावधान इसे वैधानिक स्वाद नहीं देगा शपथ पत्र प्रस्तुत करने में प्रतिवादी की कार्रवाई के रूप में 24.4.2014 नियमों में अपेक्षित संशोधन के परीक्षण को पूरा नहीं करेगा जैसा कि कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है. हालांकि यह

देखा जा सकता है कि राज्य सरकार बनी रहेगी इस न्यायालय में इसके द्वारा दायर 24.4.2014 के हलफनामे से बंधे.

44. मैं एपेक्स कोर्ट लार्सन एंड टूब्रो का मामला (सुप्रा) जबकि महाराष्ट्र मूल्य वर्धित नियम 58 की वैधता पर विचार परिस्थितियों, एक प्रावधान को पढ़ने के सिद्धांत को लागू किया था इसकी संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए. *MVAT* नियमों के नियम 58 2005, अन्य बातों के साथ, बिक्री मूल्य और खरीद के निर्धारण के लिए प्रदान करते हैं माल में संपत्ति के हस्तांतरण द्वारा बिक्री के संबंध में मूल्य (चाहे वह हो अच्छा या किसी अन्य रूप में) किसी कार्य के निष्पादन में शामिल अनुबंध. उप नियम (1) और (1 ए) जो प्रासंगिक है, इस प्रकार पढ़ता है: -

माल में संपत्ति (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य में प्रपत्र) एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल हो सकता है से निम्नलिखित कटौती को प्रभावित करके निर्धारित किया जाता है पूरे अनुबंध का मूल्य, इसलिए कटौती से संबंधित राशियों के लिए उक्त कार्य अनुबंध से संबंधित है: -  
(ए) के निष्पादन के लिए श्रम और सेवा शुल्क काम करता है;

2. 2851.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)  
उप-अनुबंध के लिए मूल्य के माध्यम से भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, तो उपमहाद्वीपों को;
3. किराया या अन्यथा, मशीनरी प्राप्त करने के लिए शुल्क और कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए उपकरण;
4. पानी, बिजली, ईंधन जैसे उपभोग्य सामग्रियों की लागत कार्य अनुबंध के निष्पादन में, वह संपत्ति जिसमें है कार्यों के निष्पादन के दौरान स्थानांतरित नहीं किया गया अनुबंध;
5. तक ठेकेदार की स्थापना की लागत जो उक्त श्रम की आपूर्ति के लिए भरोसेमंद है और सेवाएं;
6. इसी तरह के अन्य खर्च उक्त आपूर्ति से संबंधित हैं श्रम और सेवाएं, जहां श्रम और सेवाएं हैं संपत्ति के उक्त हस्तांतरण के बाद;
7. ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ इस हद तक कि यह भरोसेमंद है उक्त श्रम और सेवाओं की आपूर्ति के लिए: बशर्ते कि जहां ठेकेदार ने उन खातों को बनाए नहीं रखा है जो विभिन्न कटौती के उचित मूल्यांकन को सक्षम करते हैं ऊपर या जहां आयुक्त को लगता है कि खाते हैं ठेकेदार द्वारा बनाए रखा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं हैं या समझदार, ठेकेदार या, जैसा भी मामला हो आयुक्त उपरोक्त के अनुसार कटौती के बदले में हो सकता है तालिका में दिए गए अनुसार एकमुश्त कटौती प्रदान करें नीचे और माल की बिक्री मूल्य के अनुसार निर्धारित करें संपत्ति के उक्त हस्तांतरण के समय.

टेबल

सीनियर. नहीं	काम का प्रकार अनुबंध	से कटौती की जाने वाली राशि अनुबंध मूल्य (एक के रूप में व्यक्त किया गया अनुबंध मूल्य का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
1 से 15	XX XX XX	XX XX

(1 ए) एक निर्माण अनुबंध के मामले में, जहां साथ में अचल संपत्ति, भूमि या, जैसा भी मामला हो, ब्याज भूमि में, अचल संपत्ति अंतर्निहित है माल में, और संपत्ति (चाहे माल के रूप में)

*CUD डेवलपर लिमिटेड, KARNAL v. हरियाणा और 286 अन्य लोगों की स्थिति (अजय कुमार मित्तल, जे।)*

या किसी अन्य रूप में) के निष्पादन में शामिल निर्माण अनुबंध भी क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है इस नियम के तहत कर के लिए ऐसा हस्तांतरण उत्तरदायी है. का मूल्य स्थानांतरण के समय माल की गणना के बाद की जाएगी उप-नियम (1) के तहत कटौती करना और कुल समझौते मूल्य से भूमि की लागत.

भूमि की लागत के अनुसार निर्धारित किया जाएगा दरों के वार्षिक विवरण से जुड़े दिशानिर्देश बॉम्बे स्टैम्प के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया (संपत्ति के सच्चे बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, 1995, उस वर्ष की पहली जनवरी को लागू होता है जिसमें संपत्ति बेचने का समझौता पंजीकृत है:

*XXXX; ; III*

(४५) उप-नियम (१) के तहत एमवीटी नियम, २००५ के नियम ५ (, राज्य सरकार ने कर लगाने की कटौती की विधि निर्धारित की है निर्माण अनुबंध से संबंधित कार्य अनुबंध. यह मोटे तौर पर निर्दिष्ट करता है कटौती जो पूरे अनुबंध से स्वीकार्य हैं, अन्य बातों के साथ, पर श्रम, सेवा शुल्क, योजना के लिए शुल्क, डिजाइनिंग, वास्तुकार की फीस और इसी तरह के अन्य खर्च निर्दिष्ट हैं. के लिए दरें कटौती उस तालिका में निर्दिष्ट की जाती हैं जहां ठेकेदार ने नहीं किया है उचित खातों को बनाए रखा जो उचित मूल्यांकन को सक्षम बनाता है अलग-अलग कटौती यहां बताई गई हैं. हालांकि, उप नियम (1ए) में *MVAT* रूल्स, 2005 के नियम 58 को उसमें डाला गया था अधिसूचना दिनांक 01.06.2009. नियम ने यह प्रदान किया है कि के मामले में निर्माण अनुबंध जहां अचल संपत्ति, भूमि या के रूप में मामला हो सकता है, इसमें ब्याज दिया जाना है और संपत्ति में निर्माण अनुबंध के निष्पादन में शामिल सामान भी है हस्तांतरित, तो यह अकेले माल का ऐसा हस्तांतरण है जो कर के लिए उत्तरदायी है. हस्तांतरण के समय माल के मूल्य की गणना कुल समझौते मूल्य से भूमि की लागत में कटौती करने के बाद की जानी है. भूमि की लागत निर्धारित करने की विधि भी रही है निर्दिष्ट वहां. यह निर्धारित करता है कि भूमि की लागत होगी वार्षिक में संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है बॉम्बे स्टैम्प के प्रावधानों के तहत तैयार दरों का विवरण (संपत्ति के सच्चे बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, 1995 1st पर उस वर्ष का जनवरी जिसमें संपत्ति बेचने का समझौता है पंजीकृत. नियम कर के निर्धारण के उपाय के लिए प्रदान करता है. यह चार्जिंग प्रावधान के रूप में कर के लिए कोई दायित्व नहीं बनाता है. द सुप्रीम कोर्ट में लार्सन एंड टोबुरो का मामला (सुप्रा) विशेष रूप से पढ़ा नीचे नियम 58 जो कम्प्यूटेशनल प्रावधान थे जिससे बहिष्करण

*287L.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)*

इस तरह की सर्कल दरों और छूट के आधार पर भूमि का मूल्य कटौती प्रदान की गई थी. एपेक्स कोर्ट ने इस प्रकार देखा: -

<sup>3</sup> के कर की लेवी पर माल का मूल्य होना चाहिए हालांकि कार्यों में माल को शामिल करने का समय माल में संपत्ति बाद में गुजरती है. माल की बिक्री पर कर लगाना किसी कार्य अनुबंध में तत्व माल के निगमन के बाद भी अनुमेय है, बशर्ते कर मूल्य को निर्देशित किया गया हो निगमन के समय माल की और नहीं करने के लिए *purport* अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर कर. का तरीका नियम 58 (1-ए) में प्रदान किए गए माल का मूल्यांकन पढ़ना होगा इस मापदंड को पूरा करने के तरीके में और हम नियम को पढ़ते हैं तदनुसार 58 (1-ए). महाराष्ट्र सरकार को करना है जैसा कि ऊपर बताया गया है नियम 58 (1-ए) में स्पष्टता लाएं. के अधीन यह, *MVAT* नियमों के नियम 58 (1-A) की वैधता है

46. यदि कानून के प्रावधान बिक्री कर वसूलने की मांग कर रहे हैं कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित माल के मूल्य के अलावा किसी भी राशि पर, प्रावधान होंगे अल्ट्रा वाइस के भारत का संविधान. कर की गणना मूल्य पर नहीं की जानी है तारीख के बाद और बाद में माल में संपत्ति के हस्तांतरण के मूल्य

से अधिक खरीदारों के साथ बिक्री के लिए समझौता करना. तथापि 'डिडक्टिव मेथड' के लिए सभी कटौती की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर केवल उस पर लगाया जाता है प्रवेश करने की तारीख के बाद और बाद में माल में संपत्ति के हस्तांतरण का मूल्य खरीदारों के साथ बिक्री के लिए समझौता. जहां कर योग्य टर्नओवर का पता लगाने के लिए नियमों के तहत 'घटा हुआ तरीका निर्धारित किया गया है, आमतौर पर इसमें कानून के जनादेश के अनुरूप एक अवशेष धारा शामिल होना चाहिए ताकि सभी स्थितियों को कवर किया जा सके जिसकी परिकल्पना की जा सकती है.

47. उपरोक्त के मददेनजर, अनिवार्य रूप से, अचल का मूल्य संपत्ति और किसी भी अन्य चीज के प्रवेश की तारीख से पहले किया गया बिक्री के समझौते को समझौते के मूल्य से बाहर रखा जाना है. मूल्य एक डेवलपर के मामले में एक काम के अनुबंध में माल आदि के आधार पर जिनमें से वैट लगाया जाता है, उन कार्यों में शामिल किए जाने के समय माल का मूल्य होगा, जहां माल में संपत्ति बाद में गुजरती है. इसके अलावा, वैट को माल के मूल्य पर निर्देशित किया जाना है निगमन और यह अचल के हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए नहीं होना चाहिए संपत्ति. नतीजतन, नियमों के नियम 25 (2) को मान्य माना जाता है इसे नीचे की सीमा तक पढ़ने से संकेत मिलता है और इसके अधीन है 24.4.2014 को अपने हलफनामे से बंधी राज्य सरकार

*CUD डेवलपर लिमिटेड, KARNAL v. हरियाणा और 288 अन्य लोगों की स्थिति (अजय कुमार मित्तल, जे।)*

राज्य सरकार नियमों में आवश्यक परिवर्तन लाएगी उपरोक्त टिप्पणियों के साथ सहमति.

48. अधिनियम की धारा 42 को चुनौती के मुद्दे पर ध्यान देना याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील के अनुसार चिंतित है माल होने पर डेवलपर पर वैट देयता का आकलन करना उप-ठेकेदार द्वारा हस्तांतरित राज्यों के स्पष्ट उल्लंघन में था सातवीं अनुसूची की पावर वीड एंटी 54 सूची II. इसलिए, जिस प्रावधान में कर का मूल्यांकन किया जाना था, उसके हाथों में डेवलपर्स यहां तक कि जहां संपत्ति उप द्वारा स्थानांतरित की गई थी ठेकेदार स्पष्ट रूप से कानून में अस्थिर था और उसे खारिज करने के लिए उत्तरदायी था.
49. अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के तहत, जहां काम करता है ठेकेदार एक उप के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्य प्राप्त करता है ठेकेदार, चाहे पूरे या आंशिक रूप से, यह संयुक्त और कई होगा ठेकेदार और उप-ठेकेदार की देयता. का उप-धारा (2) धारा 42 में स्पष्ट किया गया है कि एक ठेकेदार किसी के अधीन नहीं होगा एक उप-ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया और उसका मूल्यांकन अंतिम हो गया. इस प्रावधान केवल राजस्व के हित की स्थिति में सुरक्षा करता है कर के अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए उप ठेकेदार की ओर से विफलता ठेकेदार के साथ उप ठेकेदार द्वारा दर्ज किए गए लेनदेन का सम्मान. इस प्रकार, प्रावधान को किसी भी तरीके से मनमाना, भेदभावपूर्ण या अनुचित नहीं कहा जा सकता है. के लिए सीखा वकील का विवाद इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को निरस्त कर दिया गया.
50. समान रूप से, अधिनियम की धारा 9 की वैधता को चुनौती और 2014 के सीडब्ल्यूपी नंबर 7720 में नियमों के नियम 49 (एम / एस एबीडब्ल्यू सनसिटी वी. हरियाणा राज्य) को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. नियम और धारा के नियम 8 9 अधिनियम के 9 में रचना कर के तहत एकमुश्त कर की योजना का प्रावधान है योजना जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से वैकल्पिक है. डीलर किसी के अधीन नहीं है इस योजना की सदस्यता के लिए बाध्य कर्तव्य. के तहत इसी तरह के प्रावधान 1973 अधिनियम को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था तिरथ राम आहूजा बनाम हरियाणा राज्य<sup>16</sup> अधिनियम की धारा 9 नियम 49 के साथ पढ़ी जाती है नियमों और परिपत्र दिनांक 10.2.2014 निर्धारण के लिए प्रदान करते हैं रचना योजना के तहत कर जो वैकल्पिक है और नहीं है वैट लगाने के प्रावधान। एक बार एक डीलर



के लिए विरोध करता है रचना योजना जो वैकल्पिक है, उसे विभिन्न लाभ और विशेषाधिकार मिलते हैं जो अन्यथा सामान्य वैंट डीलरों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। मैं ऐसी स्थिति, एपेक्स कोर्ट के फैसले के मददेनजर

<sup>16</sup> (1991) 83 एसटीसी 523

289 I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

कुथट्टुकुलम लिगस बनाम बिक्री कर के उपायुक्त" इन प्रावधानों के तहत कर देयता निर्धारित करने की विधि नहीं हो सकी ऐसे डीलर से पूछताछ की जाए. उपरोक्त के मददेनजर, परिपत्र दिनांकित 10.2.2014 को दोष नहीं दिया जा सकता है.

51. अंत में, आमतौर पर हम प्रारंभिक को बनाए रखेंगे वैकल्पिक उपाय की आपत्ति लेकिन प्राथमिक चुनौती के मददेनजर अधिनियम की धारा 2 (1) (zg) और नियम 25 (2) की व्याख्या की वैधता (i) नियमों की, हमने इन याचिकाओं में इस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता महसूस की.
52. मामले के कानून का ढेर प्रस्ताव के लिए एक संकेतक है जहां भी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, रिट कोर्ट होना चाहिए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने में घृणा. हालांकि, कुछ अपवादों को एपेक्स कोर्ट के विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा उकेरा गया है और उच्च न्यायालय भी.
53. इस न्यायालय की एक प्रभाग बैंच जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड और एक और बनाम हरियाणा राज्य और अन्य<sup>18</sup> विचार करने के बाद एपेक्स कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के विभिन्न उच्चारण एक्स्टेंसो में विषय, रिट क्षेत्राधिकार के अभ्यास से संबंधित मामले में वैकल्पिक उपाय के अपवादों को निर्धारित किया गया है: -

<sup>3)</sup> **URP** ऐली विभिन्न न्यायिक मिसालें, ऊपर वर्णित, इस न्यायालय की राय है कि एक याचिका के गैर-मनोरंजन के लिए एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता संविधान का अनुच्छेद 226 सार्वभौमिक नहीं हो सकता आवेदन. यह सच है कि आमतौर पर जब कानून एक वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है, और विशेष रूप से जब वहाँ के अधिकारों को स्थगित करने के लिए पूर्ण मशीनरी है पक्ष, जो बड़े और तथ्यों पर निर्भर करते हैं, उच्च न्यायालय को मनोरंजक और स्थगित करने से बचना चाहिए पार्टियों के अधिकारों पर, लेकिन इस सिद्धांत के लिए, वहाँ हैं कुछ अपवाद और एक नागरिक, जो सफलतापूर्वक कवर कर सकते हैं अपवादों में से किसी एक में इस मामले को नहीं दिखाया जा सकता है उच्च न्यायालय में उनके प्रवेश का निकास द्वार और मजबूर होना संबंधित अधिकारियों के समक्ष जाएं. कुछ अपवाद जिसके तहत एक याचिका अनुच्छेद 226 के तहत हो सकती है उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान का लाभ उठाए बिना वैकल्पिक उपाय तब होते हैं जब बहुत प्रावधान होते हैं कानून को चुनौती दी जा रही है अल्ट्रा वाइस का संविधान या अधिनियम के प्रति घृणा. जाहिर है,

<sup>17</sup> (2014) 72 वीएसटी 353

<sup>18</sup> (1996) 100 एसटीसी 45

अधिकार क्षेत्र वाले अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण एक अपील या संशोधन का मनोरंजन करें, जो भी उच्च हो विभाग का पदानुक्रम अधिनियम / कानून के प्रावधानों को समाप्त नहीं कर सकता है अल्ट्रा वायर्स. वे पालन करने के लिए बाध्य हैं अधिनियम और उसमें निहित प्रावधान. अन्य अपवाद तब है जब अधिनियम के तहत सर्वोच्च प्राधिकरण है कानून और उक्त के प्रश्न पर एक विशेष दृष्टिकोण लिया दृश्य सभी अधीनस्थ अधिकारियों को भी ज्ञात है जब एक अलग या विपरीत दृश्य द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय. ऐसी घटना में अपील या संशोधन का उपाय लोकप्रिय रूप से एक उपाय होगा पोल से पोल तक के रूप में जाना जाता है. अधीनस्थ अधिकारी दृश्य का पालन करने के लिए बाध्य हैं विभाग में सर्वोच्च प्राधिकरण

द्वारा व्यक्त किया गया अपील या संशोधन से निपटने के लिए अधिनियम के तहत गठित, जैसा भी मामला हो। तीसरा अपवाद तब हो सकता है जब आदेश, शिकायत की, पूरी तरह से अवैध और बिना है अधिकार क्षेत्र। ऐसा आदेश सामान्य रूप से तब होगा जब यह होगा पूरी तरह से कानून के प्रावधानों के विपरीत या जब वहाँ अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों के साथ कोई शक्ति नहीं है आदेश पास करें। फिर भी एक और अपवाद हो सकता है आदेशों को बाहरी विचारों या माला पर कार्य किया जाता है राज्य और सबसे अधिक गणमान्य व्यक्तियों के पक्ष में आरोप तुच्छ नहीं हैं और इसके विपरीत दिखाए गए हैं, प्रथम दृष्टया, अस्तित्व में होना। फिर भी एक और अपवाद हो सकता है जब वैकल्पिक उपाय समान रूप से प्रभावकारी नहीं होता है। फिर भी एक और अपवाद हो सकता है जब मामला तय नहीं किया जाता है लिमाइन और इसे सुनने के लिए कई वर्षों के बाद लिया जाता है और योग्यता पर निर्णय लिया और इस बीच सीमा की अवधि अपील दायर करने के लिए कानून के तहत निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। अपवादों को गुणा किया जा सकता है लेकिन अदालत नहीं करती है सभी अपवादों का विस्तार करने में संपूर्ण होना चाहते हैं। जैसा है ऊपर वर्णित, बड़े और, यह पर निर्भर होगा

(५४) घोषणाओं में वर्णित कानून का सिद्धांत वैकल्पिक उपाय के लिए सीखा राज्य के वकील द्वारा भरोसा किया जाता है संबंधित, अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि, तथ्यों में और परिस्थितियों की गणना यहां की गई है, रिट क्षेत्राधिकार का उपाय विशेष रूप से तब बंद नहीं किया जा सकता है जब अधिनियम की धारा 2 (1) (zg) के लिए स्पष्टीकरण (i) के वायर्स, आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा जारी किए गए नियमों और परिपत्रों के नियम 25 (2) को चुनौती दी गई है

2911.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (2)

रिट याचिकाएँ। अब तक याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत मुद्दों को उठाया है योग्यता पर उनके लेनदेन की गैर-करक्षमता के बारे में, यह खुला होगा उनके लिए इन सभी मुद्दों को मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष उठाना/ कानून के अनुसार संशोधन प्राधिकरण। यह भी खुला रहेगा याचिकाकर्ता स्टॉप शुल्क की वापसी के बारे में अपनी शिकायत को आंदोलन करने के लिए, यदि कोई भी, कानून के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी से पहले।

(५५) निष्कर्ष निकालने के लिए, कुछ रिट याचिकाओं में चुनौती है याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन आदेश द्वारा पारित किया गया है आबकारी द्वारा जारी परिपत्र पर निर्भर प्राधिकरण का आकलन और कराधान आयुक्त जबकि अन्य में, संशोधन का क्रम उसी परिसर पर अधिकार को स्वीकार कर लिया गया है। अभी भी आगे, में कुछ मामलों में, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय से संपर्क किया है स्वयं मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करना। हमारी राय में, में इन सभी मामलों, संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश और संशोधन आदेश स्वतंत्रता के साथ अलग सेट किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं कानूनी के आलोक में नए आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी सिद्धांतों को यहां बताया गया है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। अब तक ऐसे मामले जहां केवल नोटिस जारी किए गए हैं, सक्षम अधिकारी आगे बढ़ने और आदेश के अनुसार पारित करने का हकदार होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा